epaper.dehatsandesh.com

3 दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा केंद्र में एनईपी-2020 पर विस्तार व्याख्यान आयोजित

5 अल्कराज की दमदार वापसी, मेदवेदेव बनाम सितसिपास मुकाबला तय

8 बांस - ऐसी वनस्पति जिसके बहुत से हैं उपयोग

मौसम जम्मू — न्यूनतम 11 — अधिकतम 23

E-mail: dehatsandesh@gmail.com

देहात संदेश

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

वर्ष-23, जम्मू तवी, अंक-44 | जम्मू तवी, वीरवार 19 फरवरी, 2026 | मूल्य-3 रूपये- (लेह) 4 रूपये | पृष्ठ -8

आरएस पुरा बाल गृह से फरार दो पाकिस्तानी युवक गिरफ्तार

जम्मू,, 18 फ़रवरी। आरएस पुरा स्थित बाल गृह केंद्र से दो पुलिस कर्मियों को घायल कर फरार हुए दो पाकिस्तानी युवकों को बीती रात सुरक्षा बलों ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया था, जिसके बाद उन्हें पकड़कर वापस लाया गया।

सूत्रों के अनुसार, फरारी के दौरान दोनों युवकों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई थी।

गिरफ्तारी के बाद बुधवार को दोनों का उप जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

जम्मू-कश्मीर सरकार सिविल सेवा परीक्षा के लिए ऊपरी आयु सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव की कर रही जांच

जम्मू, 18 फ़रवरी। जम्मू-कश्मीर सरकार ने बुधवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (जेकेसीसीई) में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा बढ़ाने का मुद्दा विचाराधीन है।

हंदवाडा के विधायक सज्जाद गनी लोन के कटौती प्रस्ताव के जवाब में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 के नियमों के मौजूदा प्रावधानों, समग्र सेवा आवश्यकताओं, कैडर प्रबंधन संबंधी विचारों और अन्य राज्यों में अपनाए जाने वाले तुलनात्मक भर्ती मानकों के आलोक में इसकी व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए इस मुद्दे की जांच की जा रही है।

सरकार ने कहा कि एसआरओ 103/2018 जारी होने से पहले, संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए ऊपरी आयु सीमा ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लिए 30 वर्ष और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों और राज्य में स्थायी रूप से सिविल पद पर कार्यरत या कम से कम तीन वर्षों तक लगातार अस्थायी पद पर सेवा कर चुके उम्मीदवारों के लिए 32 वर्ष थी।

मंत्री ने कहा कि 2018 में जारी किए गए नियमों के अनुसार ओपन मेरिट श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 32 वर्ष, आरक्षित श्रेणियों और सेवारत उम्मीदवारों के लिए 34 वर्ष और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए 35 वर्ष निर्धारित की गई है।

भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट के लिए विश्व नेताओं का पीएम मोदी ने किया स्वागत

नई दिल्ली, 18 फ़रवरी। प्रधानमंत्री Narendra Modi ने बुधवार को यहां भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव Antonio Guterres और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रमुख Kristalina Georgieva सहित कई विश्व नेताओं का स्वागत किया।

विश्व नेताओं में श्रीलंका के राष्ट्रपति Anura Kumara Dissanayake और भूटान के प्रधानमंत्री *Tshering Tobgay भी शामिल थे। पारंपरिक वाद्ययंत्रों—ढोल, नादस्वरम और तानपुरा—की मधुर ध्वनियों के बीच उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी से हाथ मिलाकर और औपचारिक बातचीत के जरिए सभी अतिथियों का अभिनंदन किया।

मॉरीशस के प्रधानमंत्री Navinchandra Ramgoolam*, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री Andrej Plenkovic, सर्बिया के राष्ट्रपति Aleksandar Vucic, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति Sebastien Pillay, एस्टोनिया के राष्ट्रपति Alar Karis और फिनलैंड के प्रधानमंत्री Petteri Orpo का भी सुसज्जित भारत मंडपम में स्वागत किया गया।

इसके अतिरिक्त ग्रीस के प्रधानमंत्री Kyriakos Mitsotakis और गुयाना के उपराष्ट्रपति Bharrat Jagdeo भी उन नेताओं में शामिल थे जिनका प्रधानमंत्री ने अभिनंदन किया।

16 से 20 फरवरी तक आयोजित हो रहे एआई इम्पैक्ट समिट में 500 से अधिक वैश्विक एआई विशेषज्ञ, 150 शिक्षाविद और शोधकर्ता तथा 400 मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, उपाध्यक्ष और परोपकारी भाग ले रहे हैं।

इस शिखर सम्मेलन में 100 से अधिक सरकारी प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष तथा लगभग 60 मंत्री और उपमंत्री शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 में जम्मू-कश्मीर का कर्ज 1.37 लाख करोड़ रुपये, बढ़ते जीएसडीपी से संतुलन : उमर

जम्मू, 18 फ़रवरी। मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने बुधवार को बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में जम्मू-कश्मीर का कुल कर्ज 1,37,067 करोड़ रुपये आंका गया है, जो केंद्र शासित प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 48 प्रतिशत है। इस अवधि में जीएसडीपी बढ़कर 2,88,422 करोड़ रुपये हो गया है। सरकार की वित्तीय प्रबंधन रणनीति का बचाव करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि जीएसडीपी में वृद्धि से ऋण-से-जीडीपी अनुपात 51 प्रतिशत पिछले वर्ष से घटकर 48 प्रतिशत हो गया है। विधानसभा में लिखित उत्तर में उन्होंने पिछले छह वर्षों में ऋण-से-जीडीपी अनुपात का विवरण प्रस्तुत किया। वर्ष 2019-20 में देनदारियां 89,037 करोड़ रुपये थीं, जो उस वर्ष के 1,64,103 करोड़ रुपये के जीएसडीपी का 54 प्रतिशत थीं। 2020-21 में कोविड महामारी के कारण आर्थिक संकुचन हुआ, जिससे देनदारियां बढ़कर 98,244 करोड़ रुपये हो गईं और ऋण-से-जीडीपी अनुपात 59 प्रतिशत तक पहुंच गया। 2021-22 में देनदारियां 1,06,753 करोड़ रुपये हो गईं, लेकिन आर्थिक सुधार के चलते अनुपात घटकर 53 प्रतिशत रह गया। 2022-23 में देनदारियां 1,09,825 करोड़ रुपये रहीं और अनुपात घटकर 48 प्रतिशत हो गया। 2023-24 में देनदारियां 1,25,205 करोड़ रुपये तक पहुंचीं और अनुपात 51 प्रतिशत रहा। मुख्यमंत्री ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में देनदारियां 1,37,067 करोड़ रुपये अनुमानित हैं, जबकि जीएसडीपी 2,88,422 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जिससे ऋण-से-जीडीपी अनुपात फिर 48 प्रतिशत पर

आ गया उन्होंने कहा कि वर्षों में वित्तीय स्थिरता में सुधार हुआ है और आर्थिक विकास ने बढ़ते कर्ज के प्रभाव को संतुलित करने में मदद की है अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि उधारी का उपयोग अनुत्पादक खर्चों में न हो। उन्होंने कहा, धन का एक बड़ा हिस्सा पूंजीगत व्यय, बुनियादी ढांचा विकास, ऊर्जा क्षेत्र सुधार और परिसंपत्ति सृजन में लगाया गया है, जिससे दीर्घकालिक विकास क्षमता मजबूत हुई है।

एनएलयू मुद्दे पर हंगामे के बाद विधानसभा स्थगित, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर तीखी नोकझोंक

जम्मू,, 18 फ़रवरी। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बुधवार को उस समय हंगामा हो गया जब भाजपा विधायकों ने जम्मू में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) की स्थापना की मांग कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस बल प्रयोग के विरोध में प्रदर्शन किया। शोर-शराबे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

हंगामा उस समय शुरू हुआ जब सदन में मुख्यमंत्री Omar Abdullah से संबंधित अनुदानों पर चर्चा चल रही थी। भाजपा सदस्य अपनी सीटों से खड़े हो गए और सिविल सचिवालय के पास हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ तथा जम्मू में एनएलयू स्थापित करने की मांग के समर्थन में नारे लगाने लगे। एनएलयू फॉर जम्मू लिखे पर्चे लहराते हुए भाजपा विधायकों ने जम्मू क्षेत्र में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जोरदार मांग उठाई। साथ ही उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाब मांगा। तीखी बहस के बीच सत्तापक्ष के सदस्यों ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे छात्रों के प्रति वास्तविक चिंता दिखाने के बजाय राजनीतिक नाटक कर रहे हैं। इसके बाद विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच तीखे शब्दों का आदान-प्रदान हुआ। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने कहा कि पुलिस उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में काम करती है और भाजपा को यह मुद्दा उन्हीं के समक्ष उठाना चाहिए। उन्होंने सदन में टिप्पणी की, आपमें उनसे यह मुद्दा उठाने का साहस नहीं है। आपको छात्रों की कोई वास्तविक चिंता नहीं है, आप सिर्फ यहां राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं।

लगातार शोरगुल के बीच अध्यक्षीय आसन पर बैठे मुबारक गुल ने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले दिन में भाजपा विधायकों ने जम्मू विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर जम्मू में एनएलयू की स्थापना की मांग को लेकर प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। कश्मीर के बडगाम जिले में प्रस्तावित एनएलयू स्थापित किए जाने की घोषणा के बाद से जम्मू में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। इसे क्षेत्रीय असंतुलन का मुद्दा बताया जा रहा है। बुधवार को छात्रों ने विरोध मार्च निकाला, सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाए तथा लगभग आधे घंटे तक तवी पुल को जाम कर यातायात बाधित किया। बाद में पुलिस ने क्षेत्र खाली कराया।

उपराज्यपाल ने आदि शंकराचार्य मंदिर की आधारशिला रखी और कटरा के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की

जम्मू, 18 फ़रवरी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को आदि शंकराचार्य मंदिर की आधारशिला रखी और कटरा के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की जिनमें एक अंतर्राष्ट्रीय देवी संग्रहालय की स्थापना भी शामिल है।

अधिकारियों ने बताया कि यह आधारशिला समारोह शंकराचार्य मंदिर परियोजना की परिकल्पना के लगभग छह दशक बाद हो रहा है जिसे पहली बार 1967 में शुरू किया गया था। यह अत्याधुनिक मंदिर राज्यपाल के नेतृत्व में परिकल्पित एक और महत्वाकांक्षी परियोजना है।

इससे पहले रियासी जिले के कटरा में एक देवी संग्रहालय का निर्माण प्रस्तावित है जिसमें भारत भर के प्रमुख देवी तीर्थ स्थलों की प्रतिकृतियां और प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। समारोह के दौरान सिन्हा ने

कहा कि आदि शंकराचार्य ने देश भर का भ्रमण किया और चार मठों की स्थापना की। उन्होंने जम्मू और कश्मीर का भी दौरा किया था। कश्मीर के श्रीनगर में स्थित शंकराचार्य मंदिर में सैकड़ों तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने आगे कहा, अब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जिला प्रशासन और स्थानीय निवासियों ने मिलकर आदि शंकराचार्य को समर्पित एक भव्य मंदिर के निर्माण का निर्णय लिया है। स्थानीय देवता के लिए भी एक मंदिर बनाया जाएगा।

सिन्हा ने कहा कि सड़क अवसंरचना को मजबूत किया जाएगा और भूमिका मंदिर के जीर्णोद्धार और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है। अधिकारियों ने बताया कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्री शंकराचार्य जी मंदिर के निर्माण के साथ-साथ एक पहुंच मार्ग, संबंधित सार्वजनिक उपयोगिताओं और भूस्वामियों के लिए 50 व्यावसायिक दुकानों के निर्माण का प्रस्ताव रखा है जिसकी अनुमानित लागत 31.51 करोड़ रुपये है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जिन्होंने इस परियोजना को पुनर्जीवित किया ने कहा कि इससे क्षेत्र में तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी। अधिकारियों ने बताया, श्री शंकराचार्य जी मंदिर के निर्माण की अवधारणा मूल रूप से 1967 में तैयार की गई थी। 2025 के दौरान श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) और संबंधित भूस्वामियों के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। उन्होंने आगे बताया कि यह मंदिर 41 कनाल भूमि पर बनेगा जो भूस्वामियों द्वारा प्रस्तावित स्थल पर मोटर योग्य मार्ग के निर्माण और तीर्थयात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाओं जैसे शौचालय और जल स्रोतों के निर्माण के लिए दान की गई है। हाल ही में हुई बोर्ड बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों पर प्रकाश डालते हुए राज्यपाल ने कहा कि कटरा में देवी का एक अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा।

सरकार के कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 25 लाख की गई

जम्मू, 18 फ़रवरी। जम्मू कश्मीर सरकार ने स्पष्ट किया है कि 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत नियमित वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (डीसीआरजी) की अधिकतम सीमा 1 जनवरी, 2024 से 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। यह वृद्धि महंगाई भत्ता (डीईआरजी) के मूल वेतन के 50त्न तक पहुंचने के बाद की गई है। वित्त के प्रधान सचिव द्वारा जारी स्पष्टीकरण परिपत्र में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा विनियम, खंड 1 के अनुच्छेद 240-बीबी के नीचे नोट 8 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसे एसआरओ-194 दिनांक 24.04.2018 के माध्यम से जोड़ा गया था। इसमें यह प्रावधान है कि जब भी महंगाई भत्ता मूल वेतन के 50% तक बढ़ता है तो मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25% की वृद्धि होगी। दिनांक 21.05.2024 के सरकारी आदेश संख्या 178-एफ के अनुसार यह आदेश दिया गया था कि 7वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत नियमित वेतनमानों पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को 01.01.2024 से मूल वेतन के 50त्न की संशोधित दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वित्त विभाग को 01.01.2024 से महंगाई भत्ता 50त्न तक पहुंचने के परिणामस्वरूप मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में वृद्धि के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं। मामले की जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी प्रदान करने वाले नियमों के तहत निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को मौजूदा सीमा से 25% बढ़ाकर यानी 20.00 लाख रुपये (20 लाख रुपये) से बढ़ाकर 25.00 लाख रुपये (25 लाख रुपये) कर दिया जाएगा जो 01.01.2024 से प्रभावी होगा, जिस तारीख को महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% हो गया था।

श्रीनगर में यातायात की भीड़ कम करने के लिए प्रमुख सड़क और कॉरिडोर विकास परियोजनाएं शुरू की गईं : उपमुख्यमंत्री

श्रीनगर, 18 फ़रवरी। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने आज कहा कि सरकार ने श्रीनगर जिले के मुख्य और प्रमुख सड़कों पर यातायात सुचारू करने के लिए कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं और कॉरिडोर विकास कार्य शुरू किए हैं। उपमुख्यमंत्री विधानसभा में विधायक तनवीर सादिक द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने सदन को सूचित किया कि वर्तमान में विभिन्न चरणों में चल रही परियोजनाओं में नौशेरा से सौरा (केजेडपी रोड), सैदा कदल से आशाइबाग (एसएमएस रोड), देवी आंगन-हवाल रोड के अलावा आलमगिरी बाजार चौक और मिर्जा कामिल साहिब (एमके साहिब) चौक कॉरिडोर शामिल हैं।

उपमुख्यमंत्री ने कहा, श्रीनगर के भीतरी इलाकों में पुरानी सड़कों के

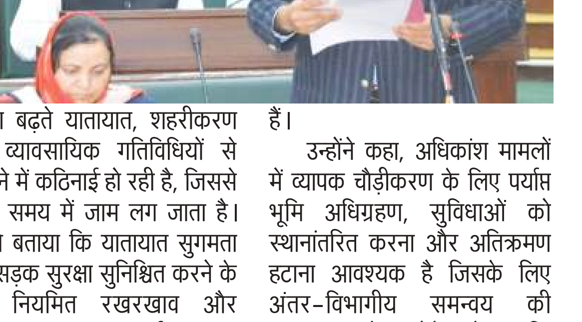

कारण बढ़ते यातायात, शहरीकरण और व्यावसायिक गतिविधियों से निपटने में कठिनाई हो रही है, जिससे व्यस्त समय में जाम लग जाता है। उन्होंने बताया कि यातायात सुगमता और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित रखरखाव और आवश्यक मरम्मत कार्य समय-समय पर किए जा रहे हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि चिन्हित सड़कों के सुधार और चौड़ीकरण के लिए प्रारंभिक आकलन किए जा चुके हैं।

उन्होंने कहा, अधिकांश मामलों में व्यापक चौड़ीकरण के लिए पर्याप्त भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं को स्थानांतरित करना और अतिक्रमण हटाना आवश्यक है जिसके लिए अंतर-विभागीय समन्वय की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि अदालती मुकदमों के कारण कुछ सड़कों पर भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है, जिससे प्रगति पर असर पड़ा है।

जम्मू और कश्मीर में केसर का उत्पादन 2024-25 में गिरकर 19.58 मीट्रिक टन हुआ

जम्मू, 18 फरवरी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जम्मू-कश्मीर में केसर का उत्पादन 2023-24 में 23.53 मीट्रिक टन से घटकर 2024-25 में 19.58 मीट्रिक टन हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हसनैन मसूदी द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में केसर की खेती का कुल क्षेत्रफल 1,116.27 हेक्टेयर पर स्थिर रहा है लेकिन उत्पादन और उत्पादकता में उतार-चढ़ाव आया है। सदन में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार केसर का उत्पादन 2020-21 में 17.33 मीट्रिक टन था जो 2021-22 में गिरकर 14.87 मीट्रिक टन और 2022-23 में 14.94 मीट्रिक टन हो गया, जो 2023-24 में 23.53 मीट्रिक टन की तेज वृद्धि दर्ज करने से पहले था। इसमें कहा गया है कि 2024-25 में यह फिर से घटकर 19.58 मीट्रिक टन रह गया। इसमें कहा गया है कि पारंपरिक और पुनर्जीवन संयुक्त रूप से औसत उत्पादकता 2022-23 में 4.02 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2023-24 में 6.33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई, लेकिन 2024-25 में घटकर 5.27 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। उन्होंने आगे कहा कि 2024-25 के दौरान केसर का निर्यात 17.82 मीट्रिक टन दर्ज किया गया जो पिछले वर्ष 20.47 मीट्रिक टन से कम है। उन्होंने कहा कि वर्ष के दौरान केसर उत्पादन का मूल्य 534.53 करोड़ रुपये था, जबकि निर्यात आय 486.43 करोड़ रुपये आंकी गई थी। पारंपरिक (गैर-पुनर्जीवित) केसर क्षेत्रों का विवरण प्रदान करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 2024-25 में इन क्षेत्रों से उत्पादन 5.02 मीट्रिक टन था, जसमें प्रति हेक्टेयर 4.5 किलोग्राम की उत्पादकता थी।

जम्मू-कश्मीर में 10 जीएमसी, एसकेआईएमएस में 219 वेंटिलेटर खराब : सरकार

जम्मू, 18 फरवरी। जम्मू-कश्मीर सरकार ने गुरुवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों और शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 219 वेंटिलेटर खराब हैं।

विधानसभा में विधायक शमीम फिरदौस के एक तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों (जीएमसी), संबंधित अस्पतालों और एसकेआईएमएस सहित अन्य प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यात्मक और निष्क्रिय वेंटिलेटर का अस्पताल-वार विवरण प्रदान किया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, कुल 877 वेंटिलेटर में से 658 काम कर रहे हैं, जबकि 219 खराब हैं।

सदन में पेश आंकड़ों के अनुसार जीएमसी

जम्मू और उससे जुड़े अस्पतालों में कुल 320 वेंटिलेटर हैं जिनमें से 209 कार्यात्मक हैं जबकि 111 गैर-कार्यात्मक हैं।

इसी तरह, जीएमसी श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में 76 वेंटिलेटर हैं, जिनमें 68 कार्यात्मक और आठ गैर-कार्यात्मक हैं, जबकि इसके अन्य संबद्ध अस्पतालों में 173 वेंटिलेटर हैं, जिनमें 44 काम नहीं कर रहे हैं। आंकड़ों में आगे कहा गया है कि जीएमसी अनंतनाग और उससे जुड़े अस्पतालों में, कुल 36 में से 26 खराब पड़े वेंटिलेटरों में से केवल 10 वेंटिलेटर ही काम कर रहे हैं।

जीएमसी बारामूला ने 41 में से दो गैर-कार्यात्मक वेंटिलेटर की सूचना दी, जबकि जीएमसी डोडा में स्थापित 27 में से 10 वेंटिलेटर खराब हैं।

जीएमसी कठुआ ने 52 में से दो गैर-कार्यात्मक वेंटिलेटर, जीएमसी राजौरी ने 54 में से तीन, और जीएमसी उधमपुर ने सभी 39 वेंटिलेटर के कार्यात्मक होने की सूचना दी। जीएमसी हंदवाड़ा ने भी सभी छह वेंटिलेटरों को कार्यात्मक बताया।

बसोहली में जल आपूर्ति मजबूत करने के लिए 242.46 करोड़ की 43 योजनाएं

अमृत 2.0 के तहत 12.60 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत

जम्मू, 18 फरवरी। बसोहली विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण जल आपूर्ति योजनाएं लागू की जा रही हैं। यह जानकारी जल शक्ति, वन, पर्यावरण एवं जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने विधानसभा में विधायक दर्शन कुमार के प्रश्न के उत्तर में दी।

मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा को बेहतर बनाने के लिए कुल 43 जल आपूर्ति योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें 42 योजनाएं जल जीवन मिशन के तहत और एक योजना नाबार्ड के अंतर्गत शामिल है। इन योजनाओं पर कुल 242.46 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इनमें से छह योजनाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं, जबकि शेष योजनाएं अंतिम चरण में हैं। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति को मजबूत करने के लिए अमृत 2.0 के तहत बसोहली नगर

के जल आपूर्ति तंत्र के विस्तार और सुधार के लिए 12.60 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई है। मंत्री ने बताया कि योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान लोगों को निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है तथा आवश्यकता पड़ने पर पानी के टैंकर भी तैनात किए जा रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की समयसीमा दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी है और सभी लंबित योजनाओं को निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाएगा। सरकार ने बसोहली क्षेत्र के सभी घरों तक सुरक्षित और नियमित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

दुल्हन

बनने जा रही हैं तो शादी के लिए खरीदें इस तरह के डिजाइनर

लहंगे

हर लड़की अपनी शादी के बड़े-बड़े सपने संजोती है कि वह सबसे फैसनेबल और स्टाइलिश दिखे।पर आजकल बाजार में हर चीज के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए है कि हर किसी के लिए शादी के सामान की अच्छी चीज को खरीदना मुश्किल हो गया है। ऐसे में अगर कपड़ो की बात की जाए तो कपडो पर की गई कढाई कपड़ो को दाम बढा देती है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि आप आपने हर फंक्शन के लिए किस तरह की पोशाक को कम दाम में खरीदे।

1. म्यूजिकल नाइट के लिए लहंगा

अगर आप अपनी म्यूजिकल नाइट में सबसे खूह सूरत दिखना चाहती है तो सुनहरे व नीले रंग का सुंदर लहंगा ही पहने। नीले रंग के इस डिजाइनर लहंगे पर तीनों रंगों का बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। इस पर लगाया गया गुलाबी व सुनहरे रंग का फीता और चोली पर सुनहरे रंग का साथ की गई कढ़ाई व नटे का दुपट्टा किसी भी रंग की लड़की को सुंदर बना सकते हैं। 2.

कॉकटेल पार्टी के लिए लहंगा

कॉकटेल पार्टी में तैयार होने के लिए आप नीला व सफेद लहंगा पहने। ऐसे लहंगे पर उम्र व फिगर वाली लड़की पर अच्छा लगता है। लहंगे व चोली पर बनाया गया फूलों का जटिल डिजाइन बहुत साफ होने के कारण आपको शाही रूप प्रदान करता हैं।

3. शादी वाले दिन लहंगा

शादी वाले दिन आप पारंपरिक लहंगे के हिसाब से लाल कुर्ती के साथ बेज रंग का लहंगा पहने। लाल रंग की कुर्ती पर की गई सुनहरे रंगी की कढाई रंगों के मिलाप को दिखाती है। इसलिए कुर्ती के साथ पहने गए बेज रंग के लहंगे पर सुनहरे रंगा का गोटा लगा हुआ लहंगा ही पहने।

4. रिसेप्शन के लिए लहंगा

अगर आप अपने रिसेप्शन पर धातुए रंग की कुर्ती के साथ काले रंग का लहंगा पहनेगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। ऐसे लहंगे में आपकी तस्वीरें बहुत ही सुंदर आएगी। ऐसे फोटोजेनिक काम के लिए लहंगा एकदम सही है। ब्लाउज का हाई नेक व चोली के सामने लगाए गए बटन आपको एक इंडो-वेस्टरन लूक देगा और आप स्टाइलिश दिखेगी। इसके साथ दुपट्टा नहीं होता है।

बजट मे रहकर खरीदें ये स्टाइलिश बैल्ट

बैल्टस को हर लड़का अपनी पैंट के साथ तथा महिलाएं अपनी स्कर्ट के साथ पहनती हैं। यह देखने में बहुत छोटी होती हैं, पर कुछ बैल्ट का दाम किसी पोशाक के मुकाबले कम नही होता। आजकल बाजार में बहुत सी स्टाइलिश बैल्ट देखने को मिलती है। इनमें से कुछ बैल्ट कपड़े की बनी होती है और कुछ चमड़े की। आज हम आपको कम बजट वाली स्टाइलिश बैल्ट के बारे में बताएगें।

1. चमडे की बैल्ट

अगर आप फॉर्मल लुक पाना चाहते हैं तो काले या भूरे रंग में चमडे की बैल्ट पहने। चमड़े की बैल्ट को बहुत ही संभाल कर रखना पड़ता है। आप इसे फॉर्मल पैंट या जीन्स के साथ पहन सकते है।

2. ब्रांडेड बैल्ट

यदि आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो ब्रांडेड बैल्ट जरूर पहने। आप इसे किसी भी सिंपल पैंट, पतलून के साथ पहन सकते है। 3. नियॉन बैल्ट

नियॉन बैल्ट रंग-बिरंगी होती है। इसे ज्यादातक स्टाइलिश लूक और फैशन स्टेटमेंट बनाने के लिए पहना जाता है। इन बैल्टस को पुरुषों व महिलाएं दोनों ही पहन सकती है।

4. टेक्स्चर्ड बैल्ट

आजकल बाजार में चमड़े और कपडे दोनों तरह की टेक्स्चर्ड बैल्ट आती है। पर इनमें से कपड़े की बैल्ट ज्यादा अच्छी होती है। इस बैल्ट की खासियत है कि इसकी पकड़ काफी आरामदायक होती है।

5. ट्रैवल बैल्ट

अगर आप ज्यादातर टुर पर जाते हैं तो आपको ट्रैवल बेल्ट पहन कर जाता चाहिए। ट्रैवल बेल्ट में 3-4 पाकिट होती हैं, जिसमें आप अपने पैसे, कार्ड, जरूरी दस्तावेज आदि संभाल सकते है। इसलिए ट्रेकिंग या छुट्टियों पर जाते समय इसे जरूर पहने।

रस्म के हिसाब से दुल्हन चुने कुछ इस तरह के बैग

शादी के बाद नई नवेली दुल्हन सभी के आकर्षण का केंद्र होती है। कपडों, गहनों से लेकर पर्स तक सभी चीजें उसकी खूबसूरती में चार-चांद लगा देते है। ऐसे में अगर पर्स डिजाइनर हो और अपनी साडी या लहंगेसे मैच करता हो तो बात ही क्या। दुल्हन को चाहिए की वह रस्मों के हिसाब से ही अपनी ड्रेस का चुनाव करे और ड्रेस के साथ मैच करता डिजाइनर पर्स लें। जो आपको खूबसूरत दिखने के साथ-साथ ग्लैमरस लुक भी दे।

1. सगाई की रस्म के समय क्लच बैग

अगर आप अपनी सगाई की रस्म में भारी साडी या लहंगा पहनने की सोच रहे है तो इसके साथ मैच करता हुआ बैग ही चुनें। सगाई की रस्म के समय आपको कल्च बैग को हाथ में पकड़ना बहुत ही आसान होगा। इसे आप कलाई पर लटका सकते है या फिर हाथ में पकड़ सकते है। 2. कॉकटेल पार्टी के लिए इंडो-वेस्टर्न लुक का बैग

अगर आप अपनी कॉकटेल पार्टी में ग्लैमरस दिखना चाहती है तो लिपटी शिफॉन की ब्लैक या लाल रंग की डिजाइनर चोली वाली साडी के साथ इंडो-वेस्टर्न लुक का बैग लें। यह आप पर बहुत ही अच्छा लगेगा।

3. शादी वाले दिन के लिए बटुआ या फिर पोटालीनुमा पर्स

आप अपनी शादी के दिन लहंगे के साथ बटुआ या फिर पोटालीनुमा पर्स का इस्तेमाल कर सकती है। इसे पकडना आपको बहुत ही आसान होगा और आप लहंगे के साथ टक कर सकती है।

4. रिसेप्शन पार्टी की शाम के लिए बैग

रिसेप्शन पार्टी के लिए आप जरदोजी या बीड्स लिए टोट बैग ही लें। इसे लेने से आप पार्टी में थोडे गलैमरस लगेगे। इस तरह के बैगस को आप साड़ी के साथ भी ले सकते है।

खूबसूरत और फ्रेश त्वचा पाने के लिए चेहरे पर लगाएं आइस क्यूब्स

आज कल हर लड़की चाहती है कि उसकी त्वचा खूबसूरत, चमकीली और मुलायम बनी रहे। ऐसे में वह अपनी त्वचा को और खूबसूरत बनाने के लिए वह तरह-तरह के प्रोडक्ट मार्किट

से ला कर इस्तेमाल करती है। पर आज हम आपको बताएगें कि आप घर पर ही आइस क्यूब्स से आप अपनी त्वचा को फ्रेश और ब्यूटीफुल बना सकती है। जाने कैसे...

1. चमकीली और स्वस्थ त्वचा

हर लड़की जवां और खूबसूरत दिखना चाहती है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप सुंदर, चमकीली और स्वस्थ त्वचा पाना चाहती है तो आइस क्यूब्स को हर रोज चाहरे पर लगाएं ।

2. आंखों की थकान मिटाने के लिए

आजकल काम का बोझ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि काम करने के दौरान हमारी आंखे थक जाती है और समय से पहले ही आंखो पर झुर्रियां पड़ जाती है। ऐसे में आंखों की थकान और झुर्रियों की समस्या को दूर तरने के लिए कॉटन के कपडे में बर्फ के कुछ टुकडे लेकर आंखों के आसपास धीरे-धीरे से घुमाएं।

3. मेकअप करने से पहले

मेकअप को ज्यादा समय तक टिकाए रखने के लिए मेकअप करने से पहले बर्फ के कुछ टुकडें लेकर कपड़े में बांधकर चेहरे पर लगाएं। ऐसा करने से आपको फ्रेशनेस का एहसास होगा।

4. स्किन टैन या त्वचा में जलन

आगर आपकी स्किन तेज धूप के कारण टैन हो गई हो या फिर जल गई हो तो ऐसे में जलन वाली जगह पर बर्फ लगाएं। बर्फ लगाने से आपको कूलिंग का एहसास होगा और टैनिंग से भी मुक्ति मिलेगी।

5. आईब्रोज करवाने के बाद होने वाली जलन

अक्सर देखा जाता है कि लड़कियां जब भी आईब्रो करवाती है तो बाद में उनहें जलन या रेडनेस होने लगती है। ऐसे में जलन और रेडनेस को कम करने के लिए आंखों के आसपास आइस क्यूब्स घुमाएं।

ट्रेगिंग्स को ट्राई करने के बाद में आप लेगिंग-जेगिंग पहनना भूल जाएगे

आजकल फैसन में ट्रेगिंग्स को बहुत ही पंसद किया जा रहा है। इसे लडकियां फॉर्मल अकेजन में पहनती है। लेगिंग्स के इस बदले ट्राउजर को आप किसी भी इवनिंग आउटिंग, फॉर्मल ब्रंच या रिलेक्स टाइम में पहन सकती हैं। बाजार में इसके बहुत से रंग मिलते है। तो आइए जानते है इन ट्रेगिंग्स के बारे में।

1. ट्राउज़र और लेगिंग से बना ट्रेगिंग्स

ट्राउज़र और लेगिंग से बनाया गया ट्रेगिंग्स उन लोगों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है, जो फैशनेबल लुक वाला आरामदायक लोअर्स पहनना पसंद करते हैं। इसे पहनकर आपको चलने-फिरने में कोई असहजता महसूस नहीं होती ।

2. ट्रेगिंग्स जेगिंग

आजकल मार्केट में ट्रेगिंग्स जेगिंग बहुत ही किफायती दामों पर मिल जाती है। ट्रेगिंग्स को आप शॉर्ट कुर्ती और स्टोल के साथ पहन सकतीं हैं। इतना ही नहीं इन्हें आप किसी भी अवसर पर पहन सकती हैं। 3. ट्रेगिंग्स को लंबे टॉप्स के साथ पहने अगर आप अपने थाइज़ को लेकर थो़डा असहज महसूस करती हैं, तो आप ट्रेगिंग्स को लंबे टॉप्स के साथ पहने ट्रेगिंग्स की फिटेड लुक को बरकरार रखने के लिए, अपने आउटफिट में थो़डी फ्लूइडटी दें या फिर इसके साथ फ्लोई टॉप्स और जैकेट पहनें।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक - नीलम सिंह गिल द्वारा देहात संदेश, गुरूद्वारा सुंदर सिंह रोड, जम्मू से प्रकाशित एवं नार्थलाईनस पबलिशर्स, 18-B, Phase- II, Industrial Estate, Gangyal, Jammu से मुद्रित। संपादक- नीलम सिंह गिल। फोन नंबरः- (95)191- 2574109 2548103 RNI Regd. No.: JKBIL/2004/13144 *Email: dehatsandesh@gmail.com, dehatsandesh@yahoo.com, dehatsandesh@rediffmail.com*

सीमावर्ती गांवों में विकास योजनाओं के लिए विशेष ग्राम सभाएं आयोजित, लोगों की भागीदारी से बनेगा अंतिम प्लान

कठुआ, 18 फरवरी (हि.स.)। जिला प्रशासन कठुआ ने भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांवों में विकास योजनाओं के निर्माण के लिए विशेष ग्राम सभाओं और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। डीसी कठुआ राजेश शर्मा ने रठुआ, गंजाल, कड्याला और गुज्जर चक्क सहित कई सीमावर्ती गांवों का दौरा कर ग्राम सभाओं की अध्यक्षता की।

इन ग्राम सभाओं का उद्देश्य स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उनकी जरूरतों और सुझावों के आधार पर मजबूत और जरूरत आधारित विकास योजनाएं तैयार करना रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लेकर अपनी समस्याएं, अपेक्षाएं और सुझाव प्रशासन के समक्ष रखे। डीसी ने कहा कि इन ग्राम सभाओं का मुख्य उद्देश्य सभी हितधारकों को साथ लेकर समग्र विकास योजना तैयार करना है, जिसमें युवाओं और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सीमावर्ती गांवों में सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ सुनिश्चित करने के लिए आगे भी ऐसे जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि बॉबिया, कड्याला, गंजाल, करोल कृष्णा, रठुआ और गुज्जर चक्क गांवों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत चिन्हित किया गया है, ताकि इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके और लोगों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।

जम्मू नगर निगम आयुक्त ने वार्ड 49 और 74 में गहन स्वच्छता एवं अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया

जम्मू, 18 फ़रवरी (हि.स.)। जम्मू नगर निगम के आयुक्त डॉ. देवांश यादव ने आज वार्ड संख्या 49 और 74 का व्यापक निरीक्षण किया, जिसमें नरवाल, बठिंडी, सुंजवान, चौवाड़ी और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। इस निरीक्षण का उद्देश्य स्वच्छता मानकों की समीक्षा करना और अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई करना था। दौरे के दौरान, आयुक्त ने मुख्य सड़कों, भीतरी गलियों, नालियों और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता का विस्तृत आकलन किया। उन्होंने चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और दौरा किए गए क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता और रखरखाव का जायजा लिया। उच्च स्वच्छता मानकों को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए डॉ. यादव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से कचरा उठाने, स्रोत पर ही कचरे का सख्त पृथक्करण करने और जलभराव और संबंधित स्वास्थ्य खतरों को रोकने के लिए नालियों की समय पर सफाई और गाद निकालने को सुनिश्चित करें उन्होंने विशेष रूप से गहरी नालियों और नालों की तत्काल सफाई पर जोर दिया, खासकर उन नालों की जिनमें बरसात के मौसम में भारी जल प्रवाह होता है और निर्देश दिया कि निवासियों को होने वाली असुविधा से बचने के लिए निवारक उपाय काफी पहले से ही किए जाएं।

सीएसआईआर-आइआइआइएम की श्रीनगर शाखा में तीन दिवसीय कौशल विकास कार्यक्रम संपन्न

जम्मू, 18 फ़रवरी (हि.स.)। सीएसआईआर-भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान (सीएसआईआर-आईआईआईएम) की श्रीनगर शाखा में 'ड्रग डिस्कवरी और बायोमेडिकल रिसर्च' विषय पर आयोजित तीन दिवसीय स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सीएसआईआर-इंटीग्रेटेड स्किल इनिशिएटिव्स के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसमें प्रारंभिक करियर के शोधार्थियों, प्रयोगशाला पेशेवरों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन मुख्य वैज्ञानिक डॉ. फैयाज मलिक और उनकी शोध टीम द्वारा किया गया। प्रतिभागियों को जैविक परीक्षणों (बायोलॉजिकल असे) और इन-विवो चूहा प्रयोगों से संबंधित प्रयोगात्मक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रयोग की रूपरेखा, असे निष्पादन, डाटा संकलन तथा छोटे पशु अध्ययनों में नैतिक मानकों का पालन जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया गया।

पहले दिन इन-विट्रो तकनीकों और असे डिजाइन पर प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सैंपल तैयारी, सेल-आधारित असे सेटअप और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक विधियों का अभ्यास कराया गया। दूसरे दिन उन्नत जैविक असे, डोज-रिस्पॉन्स विश्लेषण और एलिसा सहित विभिन्न विश्लेषणात्मक तकनीकों पर सत्र आयोजित हुए। तीसरे दिन पशु अध्ययनों से जुड़े नैतिक पहलुओं, डोजिंग तकनीक और सैंपल कलेक्शन पर प्रशिक्षण दिया गया। संस्थान के निदेशक डॉ. जाबीर अहमद ने वर्चुअल संदेश के माध्यम से प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कठोर प्रयोगशाला मानकों और शोध की गुणवत्ता पर बल दिया।

खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के छठे संस्करण की तैयारियों की समीक्षा

श्रीनगर, 18 फ़रवरी (हि.स.)। गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के छठे संस्करण के दूसरे चरण के प्रारंभ की तिथियों की घोषणा के बाद संभागीय आयुक्त कश्मीर अंशुल गर्ग ने राष्ट्रीय खेल आयोजन के सुचारू और सफल संचालन की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक व्यापक बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में उपायुक्त बारामूला, आयुक्त एसएमसी, एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर, एसएसपी सुरक्षा, एसएसपी ट्रैफिक ग्रामीण, सचिव, जम्मू-कश्मीर खेल परिषद, सीईओ जीडीए, आरटीओ और सूचना, स्वास्थ्य, पीएचई, केपीडीसीएल, परिवहन, आतिथ्य एवं प्रोटोकॉल, पर्यटन, केबल कार निगम, आईएमडी, यूएलबी, आरडीडी, ग्रामीण स्वच्छता, दूरदर्शन और अन्य संबंधित एजेंसियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

शुरुआत में जम्मू-कश्मीर खेल परिषद के सचिव ने प्रतिभागियों की संख्या, अपेक्षित वीआईपी उपस्थिति, निर्धारित कार्यक्रम, आवास की उपलब्धता, परिवहन योजना, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रचार गतिविधियों को शामिल करते हुए एक विस्तृत प्रस्तुति दी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए, संभागीय आयुक्त ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर प्रतिभागियों के आगमन, परिवहन व्यवस्था सहित कई व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

ज्योड़ियाँ बाजार में अतिक्रमण हटाने को लेकर चला विशेष अभियान

जम्मू, 18 फ़रवरी (हि.स.)। कस्बा ज्योड़ियाँ के मुख्य बाजार में आज म्युनिसिपल कमेटी की टीम द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान दुकानदारों को दुकानों के बाहर रखा गया सामान तुरंत अंदर रखने के निर्देश दिए गए, ताकि बाजार में पैदल यात्रियों और वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से हो सके। टीम ने बाजार में खड़े ई-रिक्शा चालकों को भी सख्त हिदायत दी कि वे अपने वाहन निर्धारित स्थान पर ही खड़े करें और मुख्य बाजार क्षेत्र में अव्यवस्थित पार्किंग से बचें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यातायात जाम की समस्या से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। म्युनिसिपल कमेटी के ईओ संदीप गुप्ता ने बताया कि फिलहाल दुकानदारों और ई-रिक्शा चालकों को चेतावनी देकर जागरूक किया गया है

पुलिस ने पुलवामा और शोपियां में अलग-अलग अभियानों में तीन ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार

श्रीनगर, 18 फरवरी (हि.स.)। नशीली दवाओं की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ अपनी कड़ी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने पुलवामा और शोपियां में अलग-अलग अभियानों में तीन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से पर्याप्त मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किए हैं। पीएस लिटर की एक पुलिस पार्टी ने नाका चेकिंग के दौरान गुडूरा क्रॉसिंग पर पंजीकरण संख्या जेके 13जे-1331 वाले एक वाहन को रोका। तलाशी के दौरान एक कैरी बैग से लगभग 750 ग्राम चरस पाउडर जैसा पदार्थ बरामद हुआ। वाहन के चालक की पहचान तहाब निवासी गुलाम मोहिदीन मलिक के पुत्र मुदासिर अहमद मलिक के रूप में की गई है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और अपराध में इस्तेमाल किए गए वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। एक अन्य ऑपरेशन में, पीएस पुलवामा की एक नाका पार्टी ने गुडूरा क्रॉसिंग पर एक ड्रग तस्कर को पकड़ा, जिसकी पहचान फारूक अहमद मीर, पुत्र जीएच मोहम्मद मीर, निवासी राखी शिलवत सुंबल बांदीपोरा के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके पास से करीब 137.5 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद हुआ। शोपियां में, विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस स्टेशन केलर ने एनडीपीएस अधिनियम की एफआईआर संख्या 06/2026 के तहत मामला दर्ज किया और सक्षम प्राधिकारी से सर्च वारंट प्राप्त किया। कार्यकारी मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस स्टेशन शोपियां की एक टीम ने विशरू पाईन केलर निवासी बशीर अहमद डार के घर पर छापा मारा। तलाशी के दौरान 1.880 किलोग्राम चरस और 8.570 किलोग्राम गांजा जैसा पदार्थ जब्त किया गया और आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा केंद्र में एनईपी-2020 पर विस्तार व्याख्यान आयोजित

जम्मू, 18 फ़रवरी (हि.स.)। जम्मू विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह के अंतर्गत सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (सीडीओई) द्वारा 'नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी) 2020: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति का रोडमैप' विषय पर एक विस्तार व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य एनईपी-2020 की परिवर्तनकारी सोच और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में इसकी अहम भूमिका पर विचार-विमर्श करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. मोहम्मद जुबैर कलेस, डीन, स्कूल ऑफ टीचर एजुकेशन, जम्मू क्लस्टर विश्वविद्यालय थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। सीडीओई के निदेशक प्रो. पंकज के. श्रीवास्तव ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

एम.ए. एजुकेशन की समन्वयक डॉ. अनुराधा गोस्वामी ने स्वागत भाषण में एनईपी-2020 को भारतीय शिक्षा व्यवस्था के पुनर्गठन का महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि नीति का प्रभावी क्रियान्वयन भारत को आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र बनाएगा।निदेशक प्रो. पंकज श्रीवास्तव ने कहा कि एनईपी-2020 कौशल विकास, नवाचार और रोजगारोन्मुख शिक्षा पर केंद्रित है। उन्होंने बहुविषयक शिक्षा, डिजिटल पहल और अनुसंधान को नीति की प्रमुख विशेषताएं बताया।

डीसी कार्यालय परिसर में व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

डोडा, 18 फ़रवरी (हि.स.)। डोडा के उपायुक्त (डीसी) हरविंदर सिंह ने आज डोडा डीसी कार्यालय परिसर में एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की जिसमें एसएएससीआई, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजे-जीयूए) और विरासत पहलों के तहत जिले में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया। बैठक के दौरान डीसी डोडा ने चल रहे कार्यों की क्षेत्रवार विस्तृत समीक्षा की और परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति का मूल्यांकन किया। समय पर निष्पादन, गुणवत्ता मानकों का पालन और आवंटित संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया गया ताकि इच्छित लाभ जनता तक बिना किसी देरी के पहुंच सकें। डीसी डोडा ने इन पहलों के तहत लड़कियों के छात्रावासों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे जैसे कि अलमारियां, फर्नीचर, रैक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की समय पर खरीद पर भी जोर दिया। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अध्यक्ष को परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, कार्यान्वयन के दौरान आने वाली चुनौतियों और बाधाओं को दूर करने के लिए अपनाए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी दी।

राज्य का दर्जा बहाल करने के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों पर भरोसा रखना चाहिए : बलबीर

जम्मू, 18 फ़रवरी (हि.स.)। राष्ट्रीय सम्मेलन और अन्य दलों को राज्य का दर्जा बहाल करने के संबंध में केंद्र सरकार के बार-बार दिए गए आश्वासनों पर भरोसा करना चाहिए। जम्मू-कश्मीर भाजपा के प्रवक्ता और पूर्व उपाध्यक्ष बलबीर राम रतन ने आज कहा कि राष्ट्रीय सम्मेलन और अन्य राजनीतिक दलों को केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा बहाल करने के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए बार-बार के आश्वासनों पर भरोसा रखना चाहिए।

केंद्रीय विधि एवं न्याय एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के हालिया श्रीनगर दौरे के दौरान दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जिसमें उन्होंने दोहराया था कि जम्मू-कश्मीर को यथाशीघ्र राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा बलबीर राम रतन ने कहा कि इस तरह के स्पष्ट कथनों से सभी संदेह दूर हो जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री संसद में उचित समय पर राज्य का दर्जा बहाल करने के संबंध में पहले ही स्पष्ट प्रतिबद्धता जता चुके हैं। उन्होंने कहा, जब संसद में आश्वासन दिया जा चुका है और केंद्रीय मंत्री लगातार इसकी पुष्टि कर रहे हैं तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए अनावश्यक संदेह पैदा करके लोगों को गुमराह करने का कोई कारण नहीं है। बलबीर राम रतन ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास करके अपनी निष्ठा प्रदर्शित की है।

उन्होंने पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों के सफल संचालन, रिकॉर्ड विकास व्यय, बेहतर बुनियादी ढांचे और बढ़ी हुई सुरक्षा को क्षेत्र में स्थिरता और प्रगति के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता के संकेतक के रूप में उद्धृत किया। वर्तमान में प्राथमिकता स्थायी शांति, पारदर्शी शासन और समग्र विकास सुनिश्चित करना है। वादे के अनुसार राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक परिपक्वता के लिए बार-बार बयानबाजी करने के बजाय धैर्य और रचनात्मक सहयोग की आवश्यकता है।

उत्तर रेलवे

रूचि की अभिव्यक्ति

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर रेलवे, फिरोजपुर द्वारा निर्धारित प्रोफोर्मा पर निम्नलिखित सील बंद रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती हैं:-

1	**कार्य का विवरण:** मंडल चिकित्सालय जम्मूतवी, स्वास्थ्य केंद्र कटरा, बडगाम, पठानकोट, उधमपुर के लिए नेदामिक सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए पेनल में शामिल करने हेतु प्रसिद पंजीकृत तथा लाइसेंसधारी नेदानिक केन्द्रों से रूचि की अभिव्यक्ति।
2	**अवधि:** कार्य आरम्भ होने की तिथि से दो वर्ष
3	**कार्य के अनुमानित लागत:** कोई नहीं
4	**ब्याना राशि:** कोई नहीं
5	**टेंडर फार्म की लागत:** कोई नहीं
6	**टेंडर फार्म को प्राप्त करने हेतु दिनांक तथा समय:** मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय, मंडल चिकित्सालय फिरोजपुर से किसी भी कार्य दिवस को दिनांक 13.02.2026 से 18.03.2026 तक 11:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं
7	**टेंडर बॉक्स का स्थान:** मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय, उत्तर रेलवे, फिरोजपुर
8	**टेंडर दस्तावेजों को भेजने के लिए तिथि तथा समय:** 18.03.2026 को 11:00 बजे तक। टेंडर बॉक्स को 18.03.2026 को 11:30 बजे खोला जायेगा

टिप्पणी: उपरोक्त कार्य के सामान अन्य तरह के कार्य की परिभाषा : लागू नहीं।

आबंटन: 110-241-26

सं.: 15-मेड/इन्वेस्टीगेशन दिनांक: 17.02.2026 **536/2026**

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

उत्तर रेलवे

निविदा सूचना

उप मुख्य अभियंता/निर्माण/डबलिंग, उत्तरी रेलवे, जम्मू तवी भारत के राष्ट्रपति की ओर से और निम्नलिखित कार्य के लिए एक पैकेट सिस्टम के तहत खुले ई-निविदा आमंत्रित करते हैं:-

1.	**काम और स्थान का नाम:** उधमपुर में स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स के लिए नई रेलवे बटालियन बनाने और बनाने के लिए सिविल और दूसरे काम बाकी हैं।
2.	**काम की समाप्ति अवधि:** 6 (छह) महीने।
3.	**लगभग। काम की लागत:** रु. 1,84,55,134.73
4.	**अग्रिम धन जमा करने के लिए कम से कम धन:** रु. 2,42,300/-
5.	**ई-निविदा जमा करने और निविदा निविदाएं खोलने के लिए दिनांक एवं समय:** आई.आर.ई.पी.एस वेब साइट यानी **www.ireps.gov.in** पर 17.03.2026 की तारीख को 11:30 बजे तक निविदाएं अपलोड की जा सकती हैं। बोली दाता ई-निविदा में भाग ले सकते हैं, जिसमें से, तकनीकी सहवाणिज्यिक बोलियां 17.03.2026 को 11:30 बजे खोली जाएंगी।
6.	**विस्तृत निविदा सूचना और निविदा दस्तावेज:** विस्तृत ई-निविदा सूचना उत्तरी रेलवे वेबसाइट i.e.**www.nr.indianrail.gov.in** पर उपलब्ध है और निविदा दस्तावेज **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। ऊपर निविदा दस्तावेज 03.03.2026 से 17.03.2026 तक आईआरईपीएस वेबसाइट यानी **www.ireps.gov.in** पर प्रस्ताव जमा करने के लिए उपलब्ध होगा। उपरोक्त निविदाओं के संबंध में अन्य सभी नियम और शर्तें निविदा दस्तावेज में दी गई हैं। उपरोक्त कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर विस्तृत निविदा सूचना भी देखी जा सकती है।

सं. 6-WDYCECDJAT-25-26 दिनांक: 18.02.2026 **560/2026**

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

जम्मू एवं कश्मीर सरकार
मुख्य वन संरक्षक, जम्मू का कार्यालय
(वन भवन, जम्मू)

सार्वजनिक सूचना

विषय: जम्मू एवं कश्मीर में खैर मूल्यांकन अभ्यास।

सामान्य जनहित, विशेष रूप से खैर (*Acacia catechu*) उगाने वाले किसानों की जानकारी हेतु यह सूचित किया जाता है कि जम्मू एवं कश्मीर में निजी (मिल्कियत) भूमि हेतु वर्तमान खैर प्रबंधन योजना (2016-17 से 2025-26) वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत में समाप्त हो जाएगी।

एसआरओ-111 (SRO-111) दिनांक 31.03.2016 के प्रावधानों के अनुसार, वन विभाग ने आगामी दस वर्षीय खैर प्रबंधन योजना (प्रस्तावित कटाई चक्र 2027-28 से 2036-37) के निर्माण हेतु मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

तदनुसार, जिन भी भूमि-स्वामियों/किसानों की निजी (मिल्कियत) भूमि पर खैर के पेड़ खड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपनी भूमि पर उपलब्ध खैर पौधों/पेड़ों का विवरण निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध-A) में भरकर संबंधित निकटतम रेंज अधिकारी के पास जमा करें, ताकि खैर वृक्षों की उपलब्धता का आकलन किया जा सके।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 31 मार्च 2026

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। वन एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा स्थल सत्यापन केवल पूर्ण तथा समय पर प्राप्त प्रपत्रों तक सीमित रहेगा।

अधिक जानकारी अथवा स्पष्टीकरण हेतु, जनता कार्य समय (प्रातः 10:15 बजे से अपराह्न 04:30 बजे तक) में संबंधित निकटतम रेंज अधिकारी या श्री पंकज रैना, एसएफएस (मोबाइल नं. 7006632348), नोडल अधिकारी, वन विभाग, खैर मूल्यांकन से संपर्क कर सकती है।

यह सूचना जनहित में जारी की जाती है।

DIP/J-11755/25
Dtd:18-2-2026

मुख्य वन संरक्षक, जम्मू
(सशक्त अधिकारी)

Application for Inclusion of Khair Trees in Assessment for Khair Management Plan
(To be submitted by owners of Khair trees growing on proprietary/Milkiyat lands)

To
The Divisional Forest Officer
________________Forest Division

(Recent Passport Size Photograph of Applicant)
(To be affixed here)

Sir,
Details of Khair (Acacia catechu) trees growing on my proprietary (Milkiyat) land for inclusion in the assessment report being prepared for formulation of Khair Management Plan for 2027-28 to 2036-37 are as under:

1. Particulars of the Applicant
a) Name of Applicant (with Parentage):____________________________________
b) Complete Residential Address: ____
c) Mobile Number: ____________________________________
d) Village: ____
e) Khasra Number(s): ____________________________________
f) Panchayat: ____
g) Tehsil: ____
h) District: ____________________________________
2. Name(s) of Co-sharer(s), if any (with parentage and complete address): __________________________
3. Details of Khair Trees Proposed for Assessment

Girth Class in cm (at breast Height i.e. 1.37 m/4.5')	**Number of Tree**
0-15	
15-30	
30-45	
45-60	
60-75	
75-90	
90-105	
105-120	
120-135	
135-150	
150-165	
165-180	
180 and above	

Total cultivated area under khair tree______________ Kanal_____________ Marla
4. List of Documents Enclosed:
a. Copy of Identity Proof of applicant
b. Revenue record (Khasra/Girdawari)
c. Power of Attorney/ Consent deed of co-sharer(s), if applicable
5. Declaration
I hereby declare that the particulars furnished above are true and correct to the best ofmy knowledge and belief.
I understand that furnishing false information shall render this application liable rejection and may attract action as per law.
Place:______________
Date:_______________

Signature / Thumb Impression of Applicant

For Official Use by the Range Officer:
Receipt No:
Receipt Date:
Received by (Name & Designation):
Signature & Seal:
(In Receipt No, Include: Div/Range/Block/village/Form No, should be specific to individual applicant)

जम्मू और कश्मीर आरक्षित श्रेणियाँ कर्मचारी संघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आरक्षण व संवैधानिक सुरक्षा पर उठाई आवाज

जम्मू, 18 फ़रवरी (हि.स.)। जम्मू और कश्मीर आरक्षित श्रेणियाँ कर्मचारी संघ (जेकेआरसीईए) ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र शासित प्रदेश में एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों से जुड़े आरक्षण प्रावधानों और संवैधानिक सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। संगठन के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न सामाजिक-धार्मिक संगठनों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, युवाओं और महिला विंग के सदस्यों ने भी भाग लिया। संगठन के नेताओं ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल से पदोन्नति में आरक्षण बहाल करने और वंचित वर्गों को सभी संवैधानिक गारंटियों का लाभ सुनिश्चित करने की अपील की। वक्ताओं ने कहा कि हाल के प्रशासनिक परिवर्तनों के बाद समुदायों में भ्रम की स्थिति बनी है। उन्होंने यह भी कहा कि 2014 से एससी/एसटी/ओबीसी मतदाताओं ने वादों के आधार पर समर्थन दिया था, जिनमें पदोन्नति में आरक्षण और मंडल आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन शामिल था। कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. जी.एल. थापा ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने के लिए विधायक नजीर गुरेजी का आभार व्यक्त किया और अन्य जनप्रतिनिधियों से भी मजबूत रुख अपनाने की अपील की। कार्यकारी महासचिव मोहिंदर भगत ने बजटीय प्रावधानों और कल्याण योजनाओं पर चिंता जताते हुए प्रशासन से शीघ्र संवाद की मांग की। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सादिक आजाद ने रोजगार और शिक्षा में आरक्षण सुरक्षा, पूर्व भर्ती रोस्टर की बहाली तथा मंडल आयोग की सिफारिशों के पूर्ण क्रियान्वयन की मांग रखी। दलित चेतना मंच के अध्यक्ष शाम बस्सोन ने शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अधिकारों की पैरवी जारी रखने की बात कही। संगठन ने प्रशासन से समावेशी विकास और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की।

संपादकीय

राज्य का दर्जा लौटने पर अब भी अनिश्चितता

हालाँकि केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री **Arjun Ram Meghwal** ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने के संबंध में शीघ्र निर्णय का संकेत दिया है, लेकिन फिलहाल इस दिशा में किसी ठोस कदम की उम्मीद करना जल्दबाज़ी होगी।

मेघवाल ने स्वयं इस विषय को संवेदनशील बताया है, इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि 2019 से पूर्व की स्थिति की बहाली की संभावना अभी भी कम दिखाई देती है। जम्मू-कश्मीर में पूर्ण सामान्य स्थिति अब तक स्थापित नहीं हो पाई है, भले ही राजनीतिक बयानबाज़ी में शांति लौटने का दावा किया जाता रहा हो। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच नियमित मुठभेड़ें, पहलगाम आतंकी हमला, तथा हाल ही में श्रीनगर-बारामुला राजमार्ग पर आईईडी निष्क्रिय किए जाने जैसी घटनाएँ इस बात का प्रमाण हैं कि आतंकवाद अब भी एक गंभीर समस्या बना हुआ है।

केंद्रीय मंत्री का राज्य का दर्जा लौटाने संबंधी बयान कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने वही दोहराया है जो केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने लोकसभा में कहा था। जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक पार्टियाँ लंबे समय से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रही हैं। वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों—जम्मू-कश्मीर और लद्दाख—में विभाजित कर दिया गया था।

यह भी उल्लेखनीय है कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल के शीर्ष नेतृत्व ने कई बार आश्वासन दिया है कि उपयुक्त समय पर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। हालांकि इसके लिए कोई निश्चित समयसीमा नहीं दी गई है, लेकिन यह संकेत अवश्य दिया गया है कि पूर्ण सामान्य स्थिति स्थापित होने के बाद ही यह कदम उठाया जाएगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह सर्वविदित है कि जम्मू-कश्मीर अब भी आतंकवाद से प्रभावित है। आए दिन मुठभेड़ें और शांति भंग करने की साजिशें सामने आ रही हैं। ऐसे में निकट भविष्य में राज्य का दर्जा लौटने की उम्मीद करना बिना बादलों के बारिश की आशा करने जैसा है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रधानमंत्री Narendra Modi और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में राज्य का दर्जा बहाल करने की बात कही है, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

सार रूप में कहा जा सकता है कि अरुण राम मेघवाल द्वारा शीघ्र निर्णय के संकेत के बावजूद जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने का प्रश्न अब भी अनिश्चित बना हुआ है। केंद्र ने राज्य का दर्जा पूर्ण सामान्य स्थिति से जोड़ा है, और मौजूदा सुरक्षा चुनौतियाँ तथा आतंकवाद की घटनाएँ किसी त्वरित निर्णय पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। वर्तमान परिस्थितियों और भाजपा नेतृत्व के रुख को देखते हुए, जब तक स्थायी शांति और स्थिरता स्थापित नहीं होती, तब तक शीघ्र राज्य बहाली की अपेक्षा करना समय से पूर्व होगा। इसलिए जम्मू-कश्मीर के हितों की चिंता करने वाले लोगों के लिए फिलहाल प्रतीक्षा और अवलोकन ही उचित प्रतीत होता है, क्योंकि इस समय राज्य का दर्जा लौटना एक दूर की संभावना जैसा दिखाई देता है।

यह निश्चित है कि जिस दिन केंद्र सरकार को लगेगा कि जम्मू-कश्मीर में स्थायी और दीर्घकालिक शांति स्थापित हो चुकी है, उसी दिन राज्य का दर्जा बहाल करने की घोषणा कर दी जाएगी। उससे पहले इस परिवर्तन की अपेक्षा करना निरर्थक ही होगा।

महंगाई देश के सबसे अहम आर्थिक संकेतकों में से एक

इससे सीपीआई वही महंगाई दिखाता है, जो सच में आम परिवार के बजट को प्रभावित करती है। साथ ही, उपभोग की टोकरी(कंजम्पशन बास्केट) को भी बदला गया है, ताकि सेवाओं पर बढ़ते खर्च जैसे नए रुझान दिखाई दे सकें, जो बढ़ती आय और बदलती जीवनशैली की वजह से बढ़ रहे हैं।सीपीआई को मापने का तरीका अपडेट करना भी उतना ही ज़रूरी है, जितना यह तय करना कि उसमें क्या-क्या शामिल किया जाए।

नया संशोधित सीपीआई अब अंतरराष्ट्रीय मानकों के ज्यादा करीब है, लेकिन इसमें भारत से जुड़ी खास बातें भी बनी हुई हैं। इससे भारत की महंगाई की तुलना दूसरे देशों से करना आसान हो जाता है।

आम परिवार के लिए इसका मतलब यह है कि सरकार और नीति बनाने वाले लोग यह बेहतर समझ पाते हैं कि भारत में दामों में होने वाला बदलाव दुनिया के हालात से कैसे जुड़ा है, और साथ ही यह भी ध्यान रहता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है।

सौरभगर्ग

महंगाई देश के सबसे अहम आर्थिक संकेतकों में से एक है, जिसे आम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सीधे महसूस करते हैं, जैसे घर का राशन, किराया और पेट्रोल-डीज़ल के खर्च में बढ़ोतरी से।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(सीपीआई) इसी महंगाई को मापता है। यह उन चीज़ों और सेवाओं के दाम देखता है, जिनका इस्तेमाल आम परिवार रोज़ करता है। सरल शब्दों में, सीपीआई आम आदमी की ज़िंदगी का आईना है। यह बताता है कि थाली में खाने का खर्च कितना बढ़ा, घर का किराया कितना हुआ, और काम पर जाने के लिए ईंधन कितना महंगा हुआ।

सीपीआई भले ही एक आंकड़ा लगता हो, लेकिन यह सरकार को यह समझने में मदद करता है कि लोगों पर महंगाई का असली असर क्या है। इसी आधार पर वेतन, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े फैसले किए जाते हैं, ताकि ज़रूरी चीज़ें आम लोगों की पहुंच में बनी रहें।

भारतीय रिज़र्व बैंक भी ब्याज दर और महंगाई को नियंत्रित करने जैसे फैसलों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई को ही सबसे मुख्य पैमाना मानता है। इसलिए जब सीपीआई ज़मीन की हकीकत सही तरीके से दिखाता है, तब सरकार और आरबीआई की नीतियाँ भी लोगों की असली परेशानियों के अनुसार बेहतर बन पाती हैं।

महंगाई सिर्फ दाम बढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह भी है कि दामों में बदलाव से घर के बजट पर कितना असर पड़ता है। इसलिए जितना ज़रूरी दामों को मापना है, उतना ही ज़रूरी यह भी है कि महंगाई का सूचकांक लोगों की आज की खर्च करने की आदतों को सही तरीके से दिखाए। इसी संदर्भ में भारत में सीपीआई के आधार वर्ष को 2012 से बदलकर 2024 किया जा रहा है।

पिछली बार आधार बदले जाने के बाद देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बदलाव आया है। शहरों की आबादी बढ़ी है, सेवाओं का क्षेत्र बढ़ा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण खरीदारी का तरीका बदला है और घरों का खर्च अब कई नई चीजों पर होने लगा है।

इसीलिए नया सीपीआई 2024 तैयार करने में 2023-24 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है।समय के साथ लोगों की ज़रूरतें और खर्च बदलते हैं, इसलिए सीपीआई में अलग-अलग वस्तुओं और सेवाओं को दी जाने वाली अहमियत भी बदली गई है। जिन चीजों पर अब परिवार ज़्यादा खर्च करते हैं, उन्हें सीपीआई में ज़्यादा महत्व दिया गया है,

और जिन पर खर्च कम हो गया है, उन्हें कम महत्व दिया गया है।

इससे सीपीआई वही महंगाई दिखाता है, जो सच में आम परिवार के बजट को प्रभावित करती है। साथ ही, उपभोग की टोकरी(कंजम्पशन बास्केट) को भी बदला गया है, ताकि सेवाओं पर बढ़ते खर्च जैसे नए रुझान दिखाई दे सकें, जो बढ़ती आय और बदलती जीवनशैली की वजह से बढ़ रहे हैं।सीपीआई को मापने का तरीका अपडेट करना भी उतना ही ज़रूरी है, जितना यह तय करना कि उसमें क्या-क्या शामिल किया जाए।

नया संशोधित सीपीआई अब अंतरराष्ट्रीय मानकों के ज्यादा करीब है, लेकिन इसमें भारत से जुड़ी खास बातें भी बनी हुई हैं। इससे भारत की महंगाई की तुलना दूसरे देशों से करना आसान हो जाता है।

आम परिवार के लिए इसका मतलब यह है कि सरकार और नीति बनाने वाले लोग यह बेहतर समझ पाते हैं कि भारत में दामों में होने वाला बदलाव दुनिया के हालात से कैसे जुड़ा है, और साथ ही यह भी ध्यान रहता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है।

सीपीआई के लिए आंकड़े जुटाने का तरीका भी अब लोगों की बदलती खरीदारी और खर्च की आदतों के अनुसार बेहतर बनाया गया है। जहां पहले की तरह बाजारों से दाम इकट्ठा किए जाते रहेंगे, खासकर खाने-पीने और ज़रूरी चीज़ों के, वहीं 2024 के नए ढांचे में अब कुछ सेवाओं के ऑनलाइन दाम भी शामिल किए जा रहे हैं। जैसे मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं, हवाई टिकट और कुछ अन्य सेवाओं के दाम अब ऑनलाइन स्रोतों से भी लिए जाएंगे।

नई सीपीआई श्रृंखला में अब कंप्यूटर की मदद से दाम इकट्ठा किए जा रहे हैं। इससे हाथ से होने वाली गलतियाँ कम हुई हैं और तुरंत जाँच भी हो जाती है। इससे दामों से जुड़े आंकड़ों की गुणवत्ता और समय पर उपलब्धता दोनों बेहतर हुई हैं। सीपीआई के आंकड़े सही और समय पर मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर ऐसे फैसले होते हैं, जो सीधे आम आदमी की ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं, जैसे कर्ज कितना महंगा होगा, बचत पर कितना ब्याज मिलेगा, और बढ़ती महंगाई से घर का बजट कैसे प्रभावित होगा।

नए आधार वर्ष की सीपीआई में अब कई मामलों में सरकारी स्रोतों से मिलने वाले आधिकारिक आंकड़ों का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे रेल किराया, डाक शुल्क, ईंधन के दाम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाली चीजें। इससे इन दामों को पहले से ज्यादा सही तरीके से दर्ज किया जा रहा है और बाजार सर्वे में होने वाली गलती या पक्षपात की संभावना भी कम हो जाती है।

अब सर्वे के आंकड़े, सरकारी रिकॉर्ड और डिजिटल माध्यमों से मिलने वाले दाम, तीनों को मिलाकर सीपीआई तैयार की जा रही है। यह पुरानी व्यवस्था की तुलना में बड़ा सुधार है और इससे दामों में होने वाले बदलाव की ज्यादा भरोसेमंद तस्वीर मिलती है।

इतने बड़े स्तर पर सीपीआई के आधार वर्ष में बदलाव करना एक बहुत बड़ा संस्थागत प्रयास होता है। इसमें देश भर के फील्ड दफ्तरों, सांख्यिकी विभागों और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ संस्थाओं के बीच तालमेल जरूरी होता है। इस पूरी प्रक्रिया में मेथडोलॉजी की गहराई से जाँच की जाती है, अलग-अलग विकल्पों को परखा जाता है और अर्थशास्त्रियों व विषय-विशेषज्ञों से सलाह ली जाती है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने विशेषज्ञ समूहों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और अन्य संबंधित पक्षों से बातचीत की है, ताकि किए गए बदलाव साफ, समझने में आसान और वैज्ञानिक रूप से सही हों।

टोकरी, वेटेज और आंकड़ों के स्रोत बदलने के बाद भी सीपीआई का मूल उद्देश्य वही रहता है-यानी एक परिवार की नज़र से दामों में होने वाले बदलाव को दिखाना। यह निरंतरता इसलिए ज़रूरी है, ताकि हम समय के साथ महंगाई की तुलना कर सकें। सीधे शब्दों में, सीपीआई को बेहतर बनाया जा रहा है, लेकिन उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़कर ही रखा गया है, ताकि वह नीति बनाने वालों के लिए एक भरोसेमंद मार्गदर्शक बना रहे।सीपीआई हमें यह याद दिलाता है कि हर आंकड़े के पीछे करोड़ों लोगों की असली ज़िंदगी छिपी होती है। आखिरकार, आंकड़े लोगों के लिए ही होते हैं। यह चुपचाप यह दिखाता है कि दामों में बदलाव हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करता है और सरकार की नीतियों को दिशा देता है। आधार वर्ष में चल रहे संशोधन के ज़रिये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया है कि सीपीआई सही, समय के अनुसार अपडेट और लंबे समय तक एक-जैसे तरीके से मापा गया रहे। ताकि सीपीआई सिर्फ एक संख्या न होकर, पूरे देश के लोगों की असली ज़िंदगी की सच्चाई दिखाने वाला आईना बना रहे।

(लेखक सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव हैं, यह उनके निजी विचार हैं)

बांग्लादेश सरकार में हिंदु समुदाय के सांसदों को मंत्री बनाने के निहितार्थ

– डॉ. रमेश ठाकुर

पड़ोसी देश बांग्लादेश में तारिक रहमान की अगुवाई में नई सरकार शपथ ले चुकी है। खास बात ये है नयी सरकार में दो हिंदू सांसदों को मंत्री बनाया गया है। समूची दुनिया इस निर्णय को भारत के साथ प्रत्यक्ष रूप से बांग्लादेश के बिगड़े संबंधों को सुधारने की पहल के रूप में देख रही है।

इस कदम से चीन-पाकिस्तान चिढ़े भी हैं। यह उनके लिए असहज स्थिति पैदा करता है कि बांग्लादेश, भारत या उसके नजदीकियों को तवज्जो दे। लेकिन, देश के नये प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने ऐसे मंसूबों को धता बताते हुए बड़ी सूझबूझ से कदम आगे बढ़ाया। बीते कुछ महीनों में 11 हिंदुओं की बर्बरता के साथ हुई हत्या ने बांग्लादेश की न सिर्फ थू-थू करवाई बल्कि दशकों से चले आ रहे भारत के साथ उसके मधुर संबंधों को भी पटरी से उतार दिया। इसे लेकर दोनों देशों में तल्खियां बनी हुई थीं। रहमान जानते हैं अगर माहौल ऐसा ही रहा तो रिश्तों की दूरियां घटने वाली नहीं। इसपर गौर करते हुए रहमान ने अपनी कैबिनेट में हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सांसदों को अहम औहदे सौंपे ताकि रिश्तों में फिर से नरमी लाई जा सके।

शेख हसीना की सरकार के पतन के साथ ही देश के हिंदु समुदाय को जिस तरह निशाना बनाया गया और बड़ी संख्या में भीड़ की हिंसा की घटनाएं तेजी से बढ़ीं, तारिक रहमान के सामने इन घटनाओं को तत्काल रोकने की बड़ी चुनौती है। हालांकि, इन घटनाओं को रोकने के लिए वह अपने कदम तेजी से बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री रहमान सबसे पहले पूर्व की अंतरिम सरकार के मुखिया रहे मोहम्मद यूनुस के फैसलों की गहन समीक्षा करेंगे। मोहम्मद यूनुस का झुकाव भारत को परेशान करने वाली पाकिस्तान-चीन की संयुक्त खुराफाती नीतियों की ओर ज्यादा रहा था। रहमान अच्छी तरह से समझते हैं कि जबतक मोहम्मद यूनुस कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ने की हरसंभव कोशिशे की। कुछ उन्होंने की और कुछ दूसरे देशों ने करवाई।

तारिक रहमान अपनी कैबिनेट में अल्पसंख्यक हिंदू मंत्रियों की आमद के साथ बांग्लादेश में अगले पांच सालों तक स्थिर और प्रभावशाली सरकार चलाने की मंशा रखते हैं। इसी को ध्यान में रखकर जब उनकी पार्टी बीएनपी चुनावों में जीती तो सबसे पहले वह अपने धुर विरोधी विपक्षी नेता और जमात-ए-इस्लामी प्रमुख शफीकुर रहमान के बिना बुलाए ढलती शाम के बाद उनके आवास पहुंच गए। चुनावी गुस्सेबाजियों के इतर उनसे नई सरकार में सहयोग की गुजारिश की। विपक्षी नेता ने भी राजनीतिक दुश्मनी छोड़ कर अपने घर पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

इस तरह की राजनीतिक परंपरा का प्रचार-प्रसार पूरे विश्व में होना चाहिए कि चुनाव बाद विपक्ष से सत्ता पक्ष को कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये उन देशों के लिए सीख भी है जहां पक्ष-विपक्ष आपस में अनैतिकता की सभी सीमाएं लांघ रहे हैं। रहमान उस विपक्षी नेता के घर भी पहुंचे जिनकी पार्टी चुनाव में तीसरे स्थान पर रही। नेशनल सिटीजन पार्टी के नाहिद इस्लाम को भी गले लगाया और बांग्लादेश के विकास में उनसे भी सहयोग मांगा। राजनीति में ऐसी तस्वीरों का दिखना दुर्लभ होता है लेकिन बांग्लादेश में दिखी।

रहमान की जीत पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का उन्हें भाई बताना और उनकी जीत की खुशी में फूल-मिठाइयां को ढाका भेजना भी खतरे में पड़े संबंधों में रस भरने जैसा कहा जाएगा। साथ ही रहमान के शपथग्रहण समारोह में भारत सरकार की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का पहुंचना भी संबंधों को नए सिरे से गढ़ने जैसा है। भारत के खिलाफ अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए जिस तरह चीन-पाकिस्तान ने बांग्लादेश के कंधों का इस्तेमाल कर देश को सत्यानाश के रास्ते पर धकेल दिया, उसका अंदाजा नवगठित सरकार के मुखिया को है। बांग्लादेश-भारत संबंध जितने बिगड़ेंगे, दोनों देश मिलकर उतना ही फायदा उठाएंगे। चीन-पाकिस्तान की जुगलबंदी ने पूर्व की कार्यकारी सरकार को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की शह पर बंगाली और हिंदुओं को खूब लड़ाया गया लेकिन 13वें राष्ट्रीय चुनाव में हिंदू समुदाय के तीन सांसद जीते हैं- जिनमें निताई रॉय चौधरी को स्पीकर, चटगांव से जीते अधिवक्ता दीपेन दीवान को पहाड़ी क्षेत्रों के संरक्षण के लिए मंत्री और गोयेश्वर रॉय चौधरी को रेलमंत्री बनाया गया है। यह तथ्य एक उम्मीद जगाते हैं।

बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के साथ करीब एक-डेढ़ साल से देश के विभिन्न हिस्सों में हिन्दुओं के खिलाफ भीड़ की हिंसा का जो दौर चल रहा था, वो फिलहाल थमता दिख रहा है। देश की जनता को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। काफी जद्दोजहद और राजनीतिक अस्थिरता के बीच हुए आम चुनाव में बीएनपी ने बड़े अंतर से विजय हासिल की है। कुल 298 संसदीय सीटों में 297 पर चुनाव हुए, उनमें से रिकॉर्ड 209 सीटें बीएनपी ने जीतीं। दूसरे नंबर पर जमात-ए-इस्लामी रही जिसने 68 सीटें जीतीं। तारिक रहमान की नई कैबिनेट में डॉ. खलीलुर रहमान को विदेश मंत्री, सलाहुद्दीन अहमद को गृह मंत्री, डॉ. अमीर खसरू महमूद को वित्त एवं प्लानिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुल मिलाकर तारिक रहमान ने शिक्षित और बुद्धिजीवी लोगों से अपनी कैबिनेट को सजाया है। कैबिनेट में कुल 50 मंत्री हैं, जिनमें 25 कैबिनेट और 24 राज्यमंत्री हैं।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

शिवाजी ने मुगल और बीजापुर सल्तनत की नींव को खोखला कर दिया था

शिवाजी महाराज की जयंती (19 फरवरी) पर विशेष -डॉ. लोकेश कुमार

छत्रपति शिवाजी महाराज एक साहसी, कुशल रणनीतिकार और दूरदर्शी शासक के रूप में याद किए जाते हैं, जिन्होंने मराठा पहचान दी। वे मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने मुगलों और बीजापुर सल्तनत की नींव को खोखला कर दिया। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध (छापामार युद्ध) नीति का उपयोग कर मराठा साम्राज्य की स्थापना की। माना जाता है कि गोरिल्ला युद्ध महाराणा प्रताप की खोज थी, उन्होंने मुगल शासक अकबर के खिलाफ छापामार युद्ध अपना कर उनको घुटनों के बल ला दिया था।

शिवाजी को उनकी मां जीजाबाई ने न्याय, धर्म और रामायण-महाभारत की कहानियां सुनाकर एक धर्मपरायण योद्धा के रूप में तैयार किया था। समर्थ गुरु रामदास और दादाजी कोणदेव ने भी उनके व्यक्तित्व को निखारने में हरसम्भव कोशिश की। 16 साल की आयु में उन्होंने बीजापुर सल्तनत के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाकर तोरण दुर्ग पर अधिकार जमा लिया। सन 1659 में बीजापुर के सेनापति अफजल खान को कूटनीति से मार गिराया, जो उनकी पहली बड़ी सैन्य सफलता मानी गई। उनका जन्म 19 फरवरी, 1630 को हुआ था। इस कारण उनकी जयंती 19 फरवरी को मनाई जाती है।

उन्होंने गुरिल्ला युद्ध, मजबूत नौसेना और कुशल प्रशासन के साथ तोरना, प्रतापगढ़ और रायगढ़ जैसे किले जीतकर एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। 1674 में रायगढ़ में छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक के बाद धर्म, न्याय और प्रगतिशील शासन के प्रतीक बन गए, जिन्होंने भारत के इतिहास में वीरता और स्वतंत्रता की मिसाल कायम की। वे एक उत्कृष्ट प्रशासक थे। एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखीं। शिवाजी का मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैला हुआ था। प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए, शिवाजी ने जागीर प्रथा को समाप्त कर दिया और अपने अधिकारियों को नकद वेतन देना प्रारंभ किया। जागीरदारी व्यवस्था समाप्त करने के बावजूद उन्होंने विद्यालयों और मंदिरों के लिए भूमि अनुदान देना प्रारंभ किया। उनका प्रशासन एक केंद्रीकृत, सुव्यवस्थित और जनकल्याणकारी माना जाता है, जिसका मुख्य केंद्र 'अष्टप्रधान' (आठ मंत्री) नामक मंत्रिपरिषद थी।

उनके शासन की मुख्य विशेषताओं में मलिक अंबर पर आधारित भू-राजस्व प्रणाली (33-40 प्रतिशत कर), चौथ (1/4 रक्षा कर) और सरदेशमुखी (1/10 कर) वसूली, अनुशासित स्थायी सेना, किलों का विशेष महत्व, नागरिक अधिकारियों की सर्वोच्चता और धार्मिक सहिष्णुता का गुण शामिल था।

छत्रपति के प्रशासन की विशेषताएं

शिवाजी का शासन केन्द्रीयकृत शासन था। उनके पास ही सारी शक्तियाँ निहित थी। उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध अथवा नियंत्रण नहीं था। उनके आदेशों का पालन सभी को करना पड़ता था। उनके पास पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं पदच्युति करने का पूर्ण अधिकार था। व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो पता चलता है कि अपनी समकालीन तानाशाहों से बिल्कुल भिन्न थे। उन्होंने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए आम जनता की उपेक्षा नहीं की और न जनता के अधिकारों का हनन किया। कभी भी सत्ता का दुरूपयोग नहीं किया। हरसंभव तरीके से जनता की उत्थान की चेष्टा की। प्रजा के लिए कल्याण किया और प्रजाहित, प्रजा सुरक्षा, न्याय, नैतिकता और धर्म के लिए उदार भावना थी। प्रशासनिक कार्यों में सलाह के लिए आठ मंत्रियों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें पेशवा (प्रधानमंत्री) सर्वोच्च माना जाता था। अन्य मंत्री अमात्य, वकनीस, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव और न्यायाधीश थे।

आमात्य:- शिवाजी के अष्टप्रधान में दूसरा मंत्री आमात्य कहलाता था। आमात्य अर्थ विभाग का प्रधान होता था इसे मजूमदार भी कहा जाता था इसका कार्य राज्य के आय-व्यय का ब्योरा और विभिन्न प्रांतों के हिसाब-किताब की जांच पड़ताल करना था।

पैदल सेना:- पैदल सैनिकों में नवपायिकों की सबसे छोटी इकाई होती थी इसका मुख्य नायक कहलाता था। इसका वेतन साधारण होता था पांच नायकों पर एक हवलदार होता था। दो या तीन हवलदार पर एक जुमलदार होता था।

जल सेना:- शिवाजी ने अपने राज्य की रक्षा एवं जंजीरा के विरुद्ध युद्ध करने के लिए एक जल सेना का भी गठन किया था।

शिवाजी के पास 400 जहाज थे, इनमें पांच प्रकार के युद्धपोत और कुछ बड़ी-बड़ी नावें भी थीं।

अंगरक्षक की सेना: उनके पास दो हजार चुने हुए अंगरक्षक थे, जो बड़े साहसी एवं वीर होते थे। अंगरक्षक की सेना पर पूरा व्यय राज्य वहन करता था।

भू-राजस्व और कृषक कल्याण:- भूमि की पैमाइश (माप) के लिए 'काठी' का उपयोग किया जाता था। उपज का 33 प्रतिशत (बाद में 40 प्रतिशत) कर लिया जाता था। अकाल के समय किसानों को बीज और पशु खरीदने के लिए 'तकावी' (ऋण) देने की व्यवस्था कर रखी थी।

सैन्य व्यवस्था:- उन्होंने एक मजबूत, अनुशासित और स्थायी सेना बनाई। सैनिकों को जागीर के बदले नकद वेतन देना प्रारंभ किया। सेना में 'पागा' (नियमित) और 'सिलहदार' (अस्थायी) दो प्रकार के घुड़सवार थे। शिवाजी ने किलों को सामरिक महत्व का केंद्र मानते हुए प्रत्येक किले में हवलदार, सबनीस और कारखानिस नामक तीन समान रैंक के अधिकारी बनाए, ताकि एक व्यक्ति निरंकुश नहीं हो सकें। प्रशासन का केंद्र बिंदु स्वयं शिवाजी थे। वे सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु भी थे और उनकी सेना व प्रशासन में मुस्लिम अधिकारी भी महत्वपूर्ण पदों आसीन थे। न्याय व्यवस्था सरल थी, जिसमें ग्राम पंचायतें स्थानीय विवादों का निपटारा करती थीं और उच्च स्तर पर न्यायधीश व पंडितराव न्याय करते थे।

सैनिक अनुशासन: - शिवाजी के शासनकाल में मराठा सैनिक को एकत्रित करते हुए राष्ट्रीय सेना की स्थापना की थी, सैनिक राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। वे अपने देश की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। बहरहाल, हम यही कह सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज दूरदर्शी थे। शक्तिशाली होने के साथ उन्होंने जनकल्याण के कार्य किए। उनका विचार अंतिम व्यक्ति के कल्याण पर टिका था।

(लेखक, स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

दुनिया भर के पूर्व क्रिकेट कप्तानों ने इमरान खान को जेल में उचित इलाज मुहैया कराने को कहा

एजेंसी

नई दिल्ली। दुनिया भर के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कप्तानों के एक समूह ने पाकिस्तान सरकार से अपील की है कि पूर्व प्रधानमंत्री और विश्व कप विजेता कप्तान इमरान खान को जेल में तत्काल, पर्याप्त और निरंतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा उनके साथ गरिमा और मानवीय व्यवहार किया जाए।क्रिकेट कप्तानों के एक समूह ने 17 फरवरी को जारी संयुक्त बयान में इमरान खान की बिगड़ती सेहत, विशेषकर उनकी आंखों की रोशनी में गिरावट को लेकर चिंता जताई। इस अपील पर हस्ताक्षर करने वाले पूर्व कप्तानों में माइकल एथरटन, एलन बॉर्डर, माइकल ब्रियरली, ग्रेग चैपल, इयान चैपल, बेलिंडा क्लार्क, सुनील गावस्कर, डेविड गॉवर, किम ह्यूजेस, नासिर हुसैन, क्लाइव लॉयड, कपिल देव, स्टीफन वॉ और जॉन राइट शामिल हैं। बयान में कहा गया कि इमरान खान ने 1992 विश्व कप में पाकिस्तान को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी और वह विश्व क्रिकेट के महानतम ऑलराउंडरों और कप्तानों में से एक रहे हैं। राजनीतिक मतभेदों से अलग हटकर, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया और लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेता रहे हैं, इसलिए उनके साथ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवहार होना चाहिए। पूर्व कप्तानों ने अपने बयान में कहा कि खेल भावना, सम्मान और मानवता के सिद्धांतों को बनाए रखना सभी के लिए आवश्यक है, और इसी भावना से यह अपील की गई है।

युवराज समरा का ऐतिहासिक शतक, टी20 विश्व कप में रचा नया कीर्तिमान

चेन्नई। कनाडा के सलामी बल्लेबाज युवराज समरा ने पुरुष टी20 विश्व कप में इतिहास रचते हुए सहयोगी देश के पहले खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में शतक जमाया। समरा ने चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 58 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उन्होंने चौका लगाकर तीन अंकों का आंकड़ा छुआ। यह इस संस्करण का दूसरा शतक भी है। इससे पहले श्रीलंका के पाथूम निसांका ने पल्लेकेले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सैकड़ा जड़ा था। युवराज समरा ने इससे पहले केवल 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था और फिर शानदार बल्लेबाजी जारी रखते हुए शतक तक पहुंचे। 19 वर्ष और 141 दिन की उम्र में वह पुरुष टी20 विश्व कप इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। समरा की इस पारी ने न केवल कनाडा क्रिकेट को नई पहचान दी, बल्कि सहयोगी देशों के खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा का काम किया है। उनकी आक्रामक और निडर बल्लेबाजी ने बड़े मंच पर यह साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी भी देश की सीमाओं में बंधी नहीं होती।

गिरोना डर्बी में बार्सिलोना को झटका, यामाल का पेनल्टी मिस पड़ा भारी

नई दिल्ली। स्पेनिश चैंपियन बार्सिलोना को गिरोना के खिलाफ 2-1 की हार का सामना करना पड़ा, जिससे वह ला लीगा तालिका में रियल मैड्रिड से दो अंक पीछे हो गई। रियल मैड्रिड ने रियल सोसिएदाद को हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया था, लेकिन हांसी फ्लिक की टीम गिरोना के खिलाफ बढ़त कायम नहीं रख सकी।

यामाल की चूकी पेनल्टी बनी टर्निंग पॉइंट

पहले हाफ में दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन गोल नहीं हो सका। बार्सिलोना को बढ़त का सुनहरा मौका तब मिला जब डानी ओल्मो को बॉक्स में गिराया गया और पेनल्टी मिली। हालांकि युवा स्टार लामिन यामाल ने स्पॉट-किक पोस्ट पर मार दी। 59वें मिनट में पाउ क्यूबर्सी ने जूल्स कुंडे के क्रॉस पर हेडर से बार्सिलोना को बढ़त दिलाई। लेकिन गिरोना ने जल्द ही वापसी कर ली।

लेमार और बेल्ट्रान ने पलटा मैच

थॉमस लेमार ने व्लादिस्लाव वानात के पास पर गोल कर स्कोर बराबर किया। इसके बाद गिरोना का आत्मविश्वास बढ़ गया। 87वें मिनट में फ्रान बेल्ट्रान ने बॉक्स के बाहर से शानदार शॉट लगाकर गिरोना को 2-1 की बढ़त दिलाई। इस गोल से पहले कुंडे पर फाउल को लेकर बार्सिलोना ने आपत्ति जताई, लेकिन रेफरी ने खेल जारी रखा।

रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में शमी का कहर, इरफान पठान ने की जमकर तारीफ

कल्याणी : भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 के सेमीफाइनल में बंगाल की ओर से खेलते हुए जम्मू-कश्मीर के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। बंगाल क्रिकेट अकादमी ग्राउंड पर खेले जा रहे मुकाबले में शमी ने 8 विकेट लेकर 8/90 का करियर-बेस्ट आंकड़ा दर्ज किया। शमी ने नई गेंद से ही स्विंग और रफ्तार का शानदार प्रदर्शन करते हुए जम्मू-कश्मीर के दोनों ओपनरों को पवेलियन भेज दिया। उन्होंने 59वें ओवर में कनहैया वाधवन को आउट कर अपना पांचवां विकेट पूरा किया। इसके बाद 77वें ओवर में आकिब नबी का विकेट लेकर उन्होंने आठ विकेट का कारनामा पूरा किया। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने शमी की इस घातक गेंदबाजी की खुलकर तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ङ्ग पर लिखा, 'जब वर्ल्ड कप चल रहा है, तब भारत के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक मोहम्मद शमी रणजी ट्रॉफी में मेहनत कर रहे हैं। सेमीफाइनल में 8 विकेट।' 35 वर्षीय शमी घरेलू क्रिकेट में लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले महीने सर्विसेज के खिलाफ उन्होंने दूसरी पारी में 5/51 के आंकड़े दर्ज किए थे।

कतर ओपन 2026: अल्कराज़ की दमदार वापसी, मेदवेदेव बनाम सितसिपास मुकाबला तय

एजेंसी

नई दिल्ली । दोहा में खेले जा रहे कतर ओपन 2026 में विश्व नंबर एक कार्लोस अल्कराज़ ने ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने के बाद शानदार वापसी करते हुए पहले दौर में फ्रांस के आर्थर रिंदरकनेश को 6-4, 7-6 (7/5) से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया।

मेलबर्न में खिताब जीतकर करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने अल्कराज़ को 30वीं रैंकिंग वाले रिंदरकनेश के खिलाफ कड़ा मुकाबला झेलना पड़ा। दोनों सेट बेहद प्रतिस्पर्धी रहे, लेकिन स्पेनिश स्टार ने निर्णायक मौकों पर संयम बनाए रखा। 'यह मुकाबला बेहद कठिन था। आर्थर बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं। पहले दौर में कोई भी उनके खिलाफ नहीं खेलना चाहता। मैं खुश हूं कि मैंने कठिन पलों में धैर्य बनाए रखा और

सकारात्मक रहकर शानदार टेनिस खेला। '

दूसरे दौर में वैलेंटिन रॉयेर से भिड़ंत

अब अल्कराज़ का सामना दूसरे दौर में फ्रांस के 60वीं रैंकिंग वाले वैलेंटिन रॉयेर से होगा। पहले सेट में पांचवें गेम में सर्विस ब्रेक हासिल कर अल्कराज़ ने बढ़त बनाई, जबकि दूसरे सेट में रिंदरकनेश ने कड़ा प्रतिरोध किया। हालांकि टाई-ब्रेक में अल्कराज़ ने शानदार फोरहैंड विनर लगाकर मैच अपने नाम कर लिया।

अल्कराज़ के मुख्य प्रतिद्वंद्वी यानिक सिनर ड्रॉ के दूसरे हिस्से में हैं। मई 2024 में मैड्रिड में आंद्रेई रुबलेव के खिताब जीतने के बाद से, इन दोनों खिलाड़ियों की मौजूदगी वाले किसी भी टूर्नामेंट में कोई अन्य खिलाड़ी खिताब नहीं जीत पाया है।

अल्कराज़ यदि अगले दौर में जीत दर्ज करते हैं तो क्वार्टर फाइनल में उनका सामना पूर्व चैंपियन करेन खाचानोव से हो सकता है। सातवीं वरीयता प्राप्त खाचानोव ने जापान के लकी लूजर शिंतारो मोचिजुकी को तीन सेटों में हराया। वहीं ग्रीस के स्तेफानोस सितसिपास ने ट्यूनीशिया के वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी मोएज़ एचारगुई को हराकर 2023 चैंपियन दानिल मेदवेदेव से भिड़ंत तय कर ली है।

जिरी लेहेका की भी शानदार शुरुआत

चेक गणराज्य के जिरी लेहेका, जिन्होंने पिछले साल अल्कराज़ को इसी टूर्नामेंट में बाहर किया था, ने अपने पहले मैच में अमेरिका के जेंसन ब्रूक्सबी को सीधे सेटों में हराकर दमदार शुरुआत की।

शाहपुर में राज्य स्तरीय वालीबॉल प्रतियोगिता 24 फरवरी से, प्रदेश भर से जुटेंगे 300 खिलाड़ी व ऑफिशियल

एजेंसी

धर्मशाला। जिला कांगड़ा के शाहपुर में प्रदेश भर के 300 से अधिक खिलाड़ी व ऑफिशियल जुटेंगे। शाहपुर में दो दिवसीय राज्य स्तरीय वालीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 24-25 फरवरी को किया जा रहा है। प्रतियोगिता का शुभारंभ 24 फरवरी को पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर करेंगे। इस दौरान हॉफ मैराथन का भी आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता का आयोजन वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश की जिला कांगड़ा इकाई की ओर से किया जा रहा है। प्रतियोगिता के समापन में कांगड़ा-चंबा के सांसद डॉ राजीव भारद्वाज कर विजेताओं को सम्मानित करेंगे। इसमें प्रदेश भर से 24 टीमें भाग लेंगी। इसमें लड़के व लड़कियों दोनों के मैच करवाये जाएंगे। संघ के जिलाध्यक्ष कमल कुमार शर्मा व संयुक्त सचिव प्रदीप शर्मा ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता में कहा कि 19 फरवरी को जिला कांगड़ा के लिए ट्रायल किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ हाफ मैराथन छह किलोमीटर तक शाहपुर से रेत तक आयोजित की जाएगी। जिसमें सभी युवा व अन्य लोग विशेष रूप से भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों की महिला व पुरुष वर्ग की टीमें प्रतियोगिता में भाग लेंगी। हर जिला से दो टीमें भाग लेने आ रही हैं। हॉफ मैराथन में पहले पांच स्थानों पर जगह बनाने वाले महिला व पुरुषों को पुरस्कृत किया जाएगा।

दिल्ली ओपन में सुमित नागल दूसरे दौर में, शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बाहर

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली ओपन 2026 में भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ी सुमित नागल ने पुरुष एकल के दूसरे दौर में जगह बना ली, जबकि टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर तब हुआ जब ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष वरीय डेन स्वीनी पहले ही मैच में बाहर हो गए। नागल ने स्पेन के डेविड जोरडा सांचिस को सीधे सेटों में 6-3, 7-5 से हराया। मुकाबला एक घंटा 27 मिनट चला। जीत के बाद नागल ने घरेलू दर्शकों के समर्थन को खास बताया और कहा कि दिल्ली में यह उनकी पहली जीत है। टूर्नामेंट का आयोजन डीएलटीए परिसर में हो रहा है और फाइनल 22 फ़रवरी को खेला जाएगा। यह एटीपी चैलेंजर टूर की चैलेंजर 75 श्रेणी का इवेंट है, जिसमें 32 एकल और 16 युगल जोड़ियां हिस्सा ले रही हैं। दिन का सबसे बड़ा उलटफेर तब हुआ जब कजाखस्तान के बेइबिट झुकायेव ने एक सेट गंवाने के बाद वापसी करते हुए स्वीनी को 6-7, 6-2, 6-2 से

हराया। अन्य मुकाबलों में जापान के रे साकामोटो ने चेन्नई ओपन चैंपियन फ्रेडरिको फेरेरा सिल्वा को हराकर प्री-क्वार्टर फ़ाइनल में प्रवेश किया। ब्रिटेन के जे क्लार्क ने पोलैंड के मैक्स कास्निकोव्स्की को मात देकर सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की। भारतीय खिलाड़ियों में मानस धमने, मनीष सुरेशकुमार और दिग्विजय सिंह पहले दौर में बाहर हो गए।नागल अब इतिहास रचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अबतक इस टूर्नामेंट के एकमात्र भारतीय एकल चैंपियन सोमदेव देववर्मन रहे हैं, जिन्होंने 2014 और 2015 में खिताब जीता था। युगल में भारत को सकेथ मायनेनी-सनम सिंह और यूकी भांबरी-महेश भूपति की जोड़ियों ने खिताब दिलाए हैं। चैलेंजर 75 स्तर के इस टूर्नामेंट में विजेता को 75 रैंकिंग अंक और 17,000 डॉलर की पुरस्कार राशि मिलेगी।

टी20 वर्ल्ड कप: स्कॉटलैंड को 7 विकेट से रौंदकर नेपाल ने टी20 वर्ल्ड कप में दर्ज की पहली जीत

एजेंसी

मुंबई। नेपाल ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 7 विकेट से जीत के साथ अपने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अभियान का समापन किया। नेपाल और स्कॉटलैंड की टीमें इस मैच से पहले ही खिताबी दौड़ से बाहर थीं। ऐसे में यह सम्मान की लड़ाई थी, जिसे जीतकर नेपाल ने टी20 वर्ल्ड कप में जीत के सूखे को आखिरकार खत्म किया। वानखेड़े स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी स्कॉटलैंड की टीम ने 7 विकेट खोकर 170 रन बनाए। इस टीम को जॉर्ज मुन्से और माइकल जोन्स की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 10 ओवरों में 80 रन जुटाए। मुन्से 29 गेंदों में 4 चौकों के साथ 27 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद जोन्स ने ब्रैंडन मैकमुलेन के साथ दूसरे विकेट के लिए 52 रन जुटाए। जोन्स 45 गेंदों में 3 छक्कों और 8 चौकों के साथ 71 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मैकमुलेन ने 25 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। इनके अलावा, मार्क वाट ने 10 रन जोड़े। विपक्षी खेमे से

सोमपाल कामी ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि नंदन यादव ने 2 विकेट निकाले। एक-एक विकेट रोहित पौडेल और कुशल भुर्तेल ने हासिल किया। इसके जवाब में नेपाल ने 19.2 ओवरों में जीत हासिल की। कुशल ने आसिफ शेख के साथ 9.1 ओवरों में 74 रन की साझेदारी की। कुशल 35 गेंदों में 4 छक्कों और 1 चौके के साथ 43 रन बनाकर आउट हुए, जबकि आसिफ ने 27 गेंदों में 2 छक्कों के साथ 33 रन की पारी खेली। यह टीम 98 के स्कोर तक अपने 3 विकेट खो चुकी थी। यहां से गुलशन झा ने दीपेंद्र सिंह के साथ चौथे विकेट के लिए 36 गेंदों में 73 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को शानदार जीत दिलाई। दीपेंद्र 23 गेंदों में 3 छक्कों और 4 चौकों के साथ 50 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि गुलशन ने 17 गेंदों में 24 रन की नाबाद पारी खेली। विपक्षी टीम से तीनों विकेट माइकल लीस्क ने हासिल किए।

पंजाब में 12 साल बाद बैलगाड़ी की दौड़ के साथ किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक शुरू

एजेंसी

चंडीगढ़। किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक लुधियाना में उत्साह और धूमधाम के साथ शुरू हुआ, जो 12 साल के अंतराल के बाद प्रसिद्ध बैलगाड़ी की दौड़ों के पुनरुत्थान को दर्शाता है। इन खेलों का उद्घाटन पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने गांव किला रायपुर के खेल स्टेडियम में किया। इन विश्व-प्रसिद्ध बैलगाड़ी की दौड़ों के फिर से शुरू होने से दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे दर्शक पंजाब और बाहर से इस रोमांचक खेल को देखने पहुंचे, जो राज्य की ग्रामीण विरासत में गहराई से जुड़े हुये हैं।

विधायक जीवन सिंह संगोवाल और डॉ. के. एन. एस. कंग के साथ कैबिनेट मंत्री खुड्डियां ने बैल-गाड़ियों की दौड़ों के सांस्कृतिक महत्व को उजागर करते हुए कहा कि यह पंजाब के ऐतिहासिक और पारंपरिक ग्रामीण जड़ों से मजबूत संबंध रखती हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह

मान को पंजाब विधानसभा में 'जानवरों पर अत्याचार की रोकथाम (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2025' को सर्वसम्मति से पारित और लागू करके इस पुनरुत्थान को संभव बनाने का श्रेय दिया, जिसने जानवरों के लिए सुरक्षा मानक पेश किए, कानूनी बाधाओं को दूर किया और इन बैलगाड़ी की दौड़ों को फिर से शुरू करने का रास्ता साफ किया। कैबिनेट मंत्री ने उम्मीद जताई कि किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक पंजाब भर में एक मजबूत खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने और राज्य के हर कोने से छिपी प्रतिभा को उजागर करने में मुख्य भूमिका निभाएगा। गुरमीत सिंह खुड्डियां ने पशु अस्पताल के लिए 30 लाख रुपये की ग्रांट की घोषणा की ताकि क्षेत्र में पशुओं के लिए उच्च-गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। किला रायपुर में 19 फरवरी तक चलने वाले इन खेलों में न केवल 12 साल के अंतराल के बाद बैलगाड़ी की दौड़ों की बहुत उम्मीद के बाद वापसी हुई है। इन खेलों में कबड्डी, हॉकी, एथलेटिक्स, साइक्लिंग, रस्साकशी और कई अन्य पारंपरिक खेल भी शामिल हैं। बैलगाड़ी की दौड़ों के पुनरुत्थान से देश और विदेश में बैठे पंजाबियों में बहुत उत्साह देखने को मिला है।

टी20 विश्व कप: बारिश ने पल्लेकेले में खेल बिगाड़ा, जिम्बाब्वे सुपर-8 में, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड बाहर

एजेंसी

पल्लेकेले। टी20 विश्व कप में सोमवार को पल्लेकेले में होने वाला मुकाबला लगातार बारिश की भेंट चढ़ गया। दिनभर रुक-रुक कर बारिश होती रही और एक भी गेंद फेंकी नहीं जा सकी। मैच रद्द होने का सबसे बड़ा फायदा जिम्बाब्वे को मिला, जिसने सुपर-8 चरण के लिए टिकट हासिल कर लिया। जिम्बाब्वे को मैच रद्द होने से 1 अंक मिला और उसके अब 5 अंक हो गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया यदि अपना आखिरी मैच जीतता है तो भी उसके 4 ही अंक होंगे। तो मैच रद्द होने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया। बारिश के कारण अंक बंटने से जिम्बाब्वे सातवीं टीम के रूप में सुपर-8 में पहुंचा। इसे के साथ अब सुपर 8 के जी 1 ग्रुप की तस्वीर भी साफ हो गई है, इस ग्रुप में भारत, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, और जिम्बाब्वे की टीम हैं। इस ग्रुप के सभी मुकाबले भारत में खेले जाएंगे। वहीं सुपर-8 ग्रुप जी2 में श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड और पाकिस्तान/यूएसए में से एक टीम शामिल होगी। इस ग्रुप के मैच कोलंबो और पल्लेकेले में आयोजित किए जाएंगे। बारिश ने भले ही एक मुकाबले का रोमांच छीन लिया हो, लेकिन टूर्नामेंट में आगे और भी दिलचस्प मुकाबले बाकी हैं। आज ही मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल और स्कॉटलैंड अपनी अभियान का समापन आमने-सामने की भिड़ंत के साथ करेंगे। सुपर-8 की तस्वीर अब लगभग पूरी हो चुकी है और नॉकआउट की दौड़ में शामिल टीमें खिताब के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही हैं।

अंतर महाविद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं का समापन, विजेता हुए पुरस्कृत

एजेंसी

प्रयागराज। ईश्वर शरण पीजी कॉलेज में अंतर महाविद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं का समापन हुआ। समापन सत्र में मुख्य अतिथि ईश्वर शरण पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर आनंद शंकर सिंह ने प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला एवं शारीरिक फिटनेस के साथ-साथ अनुशासन और टीमवर्क के महत्व को रेखांकित किया।

खेलकूद प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण और विदाई समारोह के साथ हुआ। इसमें 100, 200, 400, 800 मी. दौड़, वॉलीबॉल, गोला-फेंक, लम्बी कूद, ऊंची कूद जैसी विभिन्न स्पर्धा के विजेताओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले को पदक और शील्ड प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों को जीवन में अनुशासन तथा टीम भावना के महत्व पर जोर दिया। इन प्रतियोगिता में विभिन्न

महाविद्यालयों के लगभग 150 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। मैच का उद्घाटन 100 मीटर की दौड़ (गर्ल्स) के साथ हुआ जिसमें प्रथम स्थान रहनुमा अंसारी (सीएमपी डिग्री कॉलेज) से, 200 मीटर की दौड़ में खुशी शाहू (ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज) और 400 मीटर की दौड़ में रहनुमा अंसारी (सीएमपी डिग्री कॉलेज), 800 मीटर की दौड़ में साक्षी त्रिपाठी (एस.एस.के कॉलेज) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। लड़कों की दौड़ में 100 एवं 200 मीटर की दौड़ में हेमंत यादव (आईएसडीसी कॉलेज), 400 मीटर की दौड़ में शुभम पांडे (सीएमपी कॉलेज), 800 मीटर की दौड़ में अजय कुमार (आईएसडीसी कॉलेज) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। लम्बी कूद में लड़कों में टुन्ना कुमार (आईएसडीसी कॉलेज) तथा लड़कियों में आस्था यादव (सीएमपी डिग्री कॉलेज) ने बाजी मारी। वॉलीबॉल में सीएमपी डिग्री कॉलेज की लड़कियों ने आईएसडीसी की लड़कियों को हराकर शानदार जीत हासिल की। साथ ही, वॉलीबॉल में सीएमपी डिग्री कॉलेज के लड़कों ने आईएसडीसी को हराकर जीत हासिल की।

महाविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉ मनोज दुबे ने बताया कि पुरस्कार वितरण में महाविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर प्रो. मानसिंह, डॉ. हर्षमणि सिंह, डॉ अरविंद मिश्रा, डॉ अमित सिंह, डॉ. विवेक कुमार यादव, डॉ हिमांशु यादव, डॉ.अरविंद देव, डॉ. महेश प्रसाद राय, प्रशांत कुमार एवं अन्य सहायक प्राध्यापक उपस्थित रहे। समापन सत्र का संचालन एवं स्वागत कॉलेज के क्रीड़ा अधिकारी डॉ. एकात्मदेव ने किया। कार्यक्रम में सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन डॉ. शैलेश कुमार यादव ने किया।

यमुनानगर: रेलवे खिलाड़ी रोहित ने पारव चौधरी का रिकार्ड तोड़ा

एजेंसी

यमुनानगर। जूनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में यमुनानगर से रेलवे के खिलाड़ी रोहित तहलान ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया। चार से चौदह फरवरी तक आयोजित इस प्रतियोगिता में उन्होंने स्नैच स्पर्धा में 147 किलोग्राम भार उठाकर पूर्व रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। यह रिकॉर्ड पहले अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलक पारव चौधरी के नाम दर्ज था। रोहित ने प्रतियोगिता में कुल 321 किलोग्राम भार उठाया। क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 174 किलोग्राम वजन सफलतापूर्वक उठाया। समग्र प्रदर्शन के आधार पर उन्हें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। प्रतियोगिता के दौरान उनके तकनीकी कौशल, संतुलन और मानसिक दृढ़ता की खेल विशेषज्ञों ने सराहना की। प्रतियोगिता से लौटने पर कार्यस्थल पर उनका अभिनंदन किया गया। मुख्य कारखाना प्रबंधक जय प्रकाश ने कहा कि किसी भी संस्थान के लिए यह गर्व का क्षण होता है जब उसका कर्मचारी राष्ट्रीय स्तर पर

पहचान बनाता है। उन्होंने कर्मचारियों से नियमित व्यायाम और खेल गतिविधियों में भागीदारी का आह्वान करते हुए कहा कि स्वस्थ जीवनशैली कार्यकुशलता को बढ़ाती है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के लिए रेलवे मैदान में व्यायामशाला, बैडमिंटन कोर्ट और ओपन जिम सहित विभिन्न खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि वे अपनी शारीरिक क्षमता को विकसित कर सकें। संस्थान का उद्देश्य कर्मचारियों के स्वास्थ्य और खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। मंडल खेल अधिकारी देवर्षि श्रीवास्तव ने भी रोहित की उपलब्धि को प्रेरक बताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विश्वास जताया कि निरंतर अभ्यास और समर्पण के बल पर रोहित भविष्य में और अधिक पदक अर्जित करेंगे। इस अवसर पर सहायक खेल अधिकारी संकल्प कुमार, मंडल खेल सचिव शशि बक्शी तथा मंडल खेल सह सचिव पंकज चुघ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। समारोह में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और युवाओं को प्रतिस्पर्धात्मक खेलों की ओर प्रेरित करने पर विशेष बल दिया गया।

वैभव सूर्यवंशी 10वीं की परीक्षा देने नहीं पहुंचे, एब्सेंट मार्क किया गया; स्कूल के प्रिंसिपल का आया बयान

समस्तीपुर (बिहार) : अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता वैभव सूर्यवंशी मंगलवार को बिहार के पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल में अपनी क्लास 10 की ध्क्स्थ बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हुए और उन्हें एब्सेंट मार्क किया गया। बात करते हुए पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल एनके सिन्हा ने कहा कि सूर्यवंशी को CBSE पॉलिसी के अनुसार एब्सेंट मार्क किया गया था।सिन्हा ने कहा, 'वह आज एब्सेंट है। वह परीक्षा केंद्र पर नहीं आया है। हमने उसे CBSE की पॉलिसी के अनुसार एब्सेंट मार्क किया है... अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है, तो हमें उसे एब्सेंट मार्क करना होगा... हम उम्मीद कर रहे थे कि वह आकर परीक्षा देगा, लेकिन कई और भी जिम्मेदारियां हैं। क्रिकेट मैच या प्रैक्टिस हो सकती है... मुझे लगता है कि वह अगली परीक्षा जरूर देगा।' अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंदों पर 175 रन की मैच जिताने वाली पारी के लिए सूर्यवंशी प्लेयर ऑफ द मैच रहे, जिसमें 15 चौके और छक्के शामिल थे। उन्होंने 55 गेंदों में अपना शतक पूरा किया जो अंडर-19 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतकों में से एक है और भारत को छठी बार वर्ल्ड कप जीतने में मदद की। सूर्यवंशी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। उन्होंने 7 मैचों में 169.50 के शानदार स्ट्राइक रेट और 62.71 के औसत से 439 रन बनाए। बाएं हाथ के इस ओपनर ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के (30 छक्के) लगाए।

टी-20 विश्व कप में फिलिप्स के तूफानी अर्धशतक ने युवराज का शतक फीका किया, न्यूज़ीलैंड सुपर-8 में

एजेंसी

चेन्नई। न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने टी20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कनाडा को आठ विकेट से हराकर सुपर-8 चरण में प्रवेश कर लिया। एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में ग्लेन फिलिप्स की नाबाद 76 रन की विस्फोटक पारी ने 19 वर्षीय युवराज समरा के ऐतिहासिक शतक पर पानी फेर दिया। 174 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूज़ीलैंड की शुरुआत लड़खड़ा गई और टीम ने 30 रन पर दो विकेट गंवा दिए। लेकिन इसके बाद रचिन रवींद्र और ग्लेन फिलिप्स ने पारी को संभालते हुए मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। कीवी टीम ने 15.1 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया और लगभग पांच ओवर शेष रहते जीत दर्ज की। इस जीत के साथ न्यूज़ीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका से मिली हार का भी बदला चुका लिया। इससे पहले कनाडा ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 173 रन बनाए। टीम के लिए 19 वर्षीय युवराज समरा ने 58 गेंदों में

110 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। यह टी20 विश्व कप के इतिहास में किसी एसोसिएट देश के बल्लेबाज द्वारा बनाया गया पहला शतक है। समरा ने अपनी टीम के कुल स्कोर का 63 प्रतिशत से अधिक योगदान दिया। कप्तान दिलप्रीत बाजवा ने 36 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया। हालांकि अंतिम ओवरों में जैकब डफी और काइल जैमीसन ने अहम विकेट लेकर कनाडा को 180 के पार जाने से रोका।

लक्ष्य का पीछा करते हुए फिन एलेन ने आठ गेंदों पर 21 रन बनाकर तेज शुरुआत दिलाई, लेकिन साद बिन जफर ने टिम सिफर्ट को विकेट मेडन ओवर में आउट कर मैच में कनाडा की वापसी कराई। इसके बाद डिलोन हेलीगर ने एलेन को चलता किया और न्यूज़ीलैंड 30/2 पर दबाव में आ गया। यहीं से रचिन रवींद्र और फिलिप्स ने कमान संभाली। रवींद्र ने संयमित बल्लेबाजी करते हुए पारी को स्थिरता दी, जबकि फिलिप्स ने आक्रामक अंदाज अपनाया। फिलिप्स ने मात्र 22 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो टी20 विश्व कप में न्यूज़ीलैंड के लिए सबसे तेज अर्धशतक है। उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ शानदार शॉट्स लगाए और साद बिन जफर पर स्विच-हिट छक्का भी जड़ा।

दोनों के बीच शतकीय साझेदारी ने मैच पूरी तरह न्यूज़ीलैंड की झोली में डाल दिया। फिलिप्स ने 36 गेंदों पर नाबाद 76 रन बनाए, जबकि रवींद्र ने 59 रन की नाबाद पारी खेली। रवींद्र ने धीमी गेंद को डीप मिडविकेट की ओर पुल शॉट लगाकर टीम को जीत दिलाई।

सर्राफा बाजार के साथ ही कमोडिटी मार्केट में भी सोना-चांदी की कीमत में गिरावट

एजेंसी

नई दिल्ली। सर्राफा बाजार (बुलियन मार्केट) के साथ ही कमोडिटी मार्केट में भी आज सोना और चांदी की कीमत में गिरावट का रुख बना हुआ है। एशियाई बाजार में आज लूनर न्यू ईयर की छुट्टी की वजह से सोना और चांदी दोनों कमोडिटी में ट्रेडिंग घट गई है, जिससे इनकी कीमतों पर दबाव बना हुआ है। इसके साथ ही अमेरिकी डॉलर की मजबूती से भी सोना और चांदी की कीमत पर दबाव बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर दोपहर 12 बजे के करीब चांदी की कीमत 7,491 यानी 3.12 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,32,400 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बनी हुई थी। इसी तरह सोना 2,760 रुपये यानी 1.77 प्रतिशत फिसल कर 1,52,024 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। अंतराष्ट्रीय बाजार में भी सोना और चांदी के भाव में गिरावट का ट्रेंड बना हुआ है। अंतराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट सिल्वर लुढ़क कर 73 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि बाद में इसमें सुधार हुआ।

एयर इंडिया और लुफ्थांसा ने कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया सहयोग

नई दिल्ली। एयर इंडिया और लुफ्थांसा समूह ने आपसी सहयोग को और आगे बढ़ाते हुए एक-दूसरे के यात्रियों के लिए भारत और यूरोप में साझा कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए मंगलवार को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये। यह समझौता हाल ही में संपन्न ऐतिहासिक भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार संधि (एफटीए) से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने के उद्देश्य से किया गया है। इसके तहत एयर इंडिया और जर्मनी के लुफ्थांसा समूह की विमान सेवा कंपनियों और सहायक कंपनियों - एयर इंडिया एक्सप्रेस, ऑस्ट्रियन एयरलाइंस, ब्रसेल्स एयरलाइंस, आईटीए एयरवेज, लुफ्थांसा, स्विस इंटरनेशनल एयर लाइंस और अन्य संबद्ध एयरलाइंस समेत - के बीच संयुक्त व्यावसायिक समझौते की रूपरेखा तय की गयी है। एयर इंडिया और लुफ्थांसा समूह के बीच एक कोडशेयर समझौता पहले से है। दोनों स्टार एलायंस के सदस्य हैं। यह करार दोनों पक्षों को भारत और प्रमुख यूरोपीय बाजारों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के विकल्प तलाशने में सक्षम बनायेगा। एमओयू पर एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक कैंपबेल विल्सन और लुफ्थांसा समूह के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्स्टन श्पोर ने हस्ताक्षर किये।

रुपया दो पैसे मजबूत

मुंबई। अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया मंगलवार को दो पैसे मजबूत हुआ और कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 90.72 रुपये का बोला गया। भारतीय मुद्रा पिछले कारोबारी दिवस पर 7.50 पैसे टूटकर 90.74 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई थी रुपया आज दो पैसे की मजबूती के साथ 90.72 रुपये प्रति डॉलर पर खुला। बीच कारोबार में यह ऊपर 90.64 रुपये और नीचे 90.78 रुपये प्रति डॉलर तक गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों के भारतीय पूंजी बाजार में पैसा लगाने से रुपया मजबूत हुआ है। हालांकि दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर सूचकांक में 0.4 प्रतिशत की तेजी से भारतीय मुद्रा की बढ़त सीमित रही।

गिफ्ट सिटी में मार्च में आयेगा पहला आईपीओ

नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) गिफ्ट सिटी में मार्च के शुरुआती सप्ताह में पहला आईपीओ आने की उम्मीद है।

शीर्ष अधिकारियों के लिए कॉरपोरेट पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाली कंपनी एक्सईडी ने बताया है कि उसने सभी नियामकीय अर्हताएं पूरी करने के बाद प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए दस्तावेज (रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस) जमा कराये हैं। यह गिफ्ट सिटी का पहला आईपीओ होगा। इसमे मार्च के पहले सप्ताह में आने की संभावना है। गिफ्ट सिटी देश के भीतर ही एक विदेशी एक्सचेंज की तरह काम करता है। वहां लेनदेन डॉलर में होता है और वहां आईपीओ लाने का मुख्य उद्देश्य विदेशी निवेशकों को लुभाना है। एक्सईडी ने आईपीओ से 1.2 करोड़ डॉलर की पूंजी जुटाने का लक्ष्य रखा है। एक्सईडी को आईपीओ के लिए शेयर बाजारों से मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद उसने कंपनी रजिस्ट्रार के पास आईपीओ से संबंधित दस्तावेज भी जमा करा दिये हैं। आईपीओ के लिए दुनिया भर के प्रवासी भारतीय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक और संस्थागत निवेशक बोली लगा सकेंगे। कंपनी के शेयर एनएसई में इंटरनेशनल एक्सचेंज और गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज में सूचीबद्ध होंगे। बड़े निवेशकों को आईपीओ में निवेश का मौका पहले मिलेगा। इस प्रक्रिया के फरवरी के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।

देश में एआई में दो सालों में आएगा 200 अरब डॉलर निवेशः अश्विनी वैष्णव

एजेंसी

नई दिल्ली । केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कहा कि आने वाले दो वर्षों में भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षेत्र की पांचों परतों में 200 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश आने की उम्मीद है। जोखिम पूंजी कंपनियां गहन तकनीक स्टार्टअप्स, बड़े समाधान और अनुप्रयोगों, अत्याधुनिक मॉडल्स पर शोध और बुनियादी ढांचा और ऊर्जा परतों में निवेश कर रही हैं। इस मौके पर केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद रहे।वैष्णव ने यहां भारत मंडपम में एक सत्र में कहा कि भारत की एक बड़ी ताकत यह है कि देश की 51 प्रतिशत बिजली उत्पादन क्षमता स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की

दूरदर्शिता और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता के कारण यह संभव हुआ है। एआई के लिए ऊर्जा परत में निवेश का यह बड़ा लाभ भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा। उन्होंने एआई के संभावित खतरों को बताते हुए कहा कि वैश्विक नेताओं के बीच इस बात पर सहमति बन रही है कि एआई का इस्तेमाल अच्छे कार्यों के लिए होना चाहिए और इसके हानिकारक प्रभावों को रोकना जरूरी है। इसके लिए केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि तकनीकी और कानूनी दृष्टिकोण अपनाना होगा। भारत का कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा संस्थान कई शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर ऐसे तकनीकी समाधान तैयार कर रहा है, जो एआई के दुष्प्रभावों को रोक सकें। एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनसन हुआंग के सम्मेलन में शामिल न होने पर वैष्णव ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से आने में असमर्थता जताई, लेकिन अपनी वरिष्ठ टीम को भेजा है। एनवीडिया भारत की कई कंपनियों के साथ मिलकर एआई ढांचा और सॉफ्टवेयर के बड़े निवेश कर रहा है। वैष्णव ने कहा कि भारत अपने मजबूत आईटी सेक्टर में तकनीकी बदलाव को रणनीतिक रूप से संभाल रहा है।

सरकार, उद्योग और शिक्षा संस्थानों के सहयोग से कर्मचारियों की प्रतिभाओं को निखारना, नई प्रतिभा तैयार करना और भविष्य की पीढ़ियों को तैयार करना प्रमुख उद्देश्य है। एआई आधारित रीस्किलिंग और 100 से अधिक कॉलेजों में पाठ्यक्रम सुधारों के जरिए युवाओं को वैश्विक अवसरों के लिए तैयार किया जा रहा है।

अडाणी समूह एआई सक्षम डेटा केंद्र विकसित करने के लिए 100 अरब डॉलर निवेश करेगा

एजेंसी

नई दिल्ली। अडाणी समूह ने नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित अत्याधुनिक एआई सक्षम डेटा केंद्रों को 2035 तक विकसित करने के लिए 100 अरब अमेरिकी डॉलर (9 लाख करोड़ रुपये) का निवेश करेगा। अडाणी समूह ने नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित अत्याधुनिक एआई सक्षम डेटा केंद्रों को विकसित करने के लिए अगले 9 साल यानी 2035 तक 100 अरब यूएस डॉलर का निवेश करने की घोषणा की। यह दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत 'एनर्जी-कंप्यूट' प्रतिबद्धताओं में से एक है। समूह की प्रमुख कंपनी अडाणी एंटरप्राइजेज ने बयान में कहा कि इस पहल से 'सर्वर' निर्माण, 'क्लाउड' मंच एवं सहायक उद्योगों में अतिरिक्त 150 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश होने की उम्मीद है। इससे भारत में 250 अरब डॉलर का अनुमानित एआई अवसंरचना परिवेश तैयार होगा।

अडाणी समूह के चेयरमैन गौतम अडाणी ने कहा कि दुनिया एक ऐसी बुद्धिमत्ता क्रांति में प्रवेश कर रही है, जो पिछली किसी भी औद्योगिक क्रांति से कहीं अधिक गहन है। ऊर्जा एवं कंप्यूटर के बीच सामंजस्य स्थापित करने में निपुण राष्ट्र ही आने वाले दशक को आकार देंगे। उन्होंने कहा कि भारत नेतृत्व करने के लिए अद्वितीय स्थिति में है। गौतम अडाणी ने कहा कि अडाणी समूह में हम डेटा केंद्रों और हरित ऊर्जा में अपनी मजबूत नींव पर काम करते हुए भारत की प्रौद्योगिकी संप्रभुता पर केंद्रित पांच स्तरीय एआई ढांचे में विस्तार कर रहे हैं। एआई युग में भारत केवल उपभोक्ता नहीं रहेगा। हम बुद्धिमत्ता के विनिर्माता, विकासकर्ता एवं निर्यातक होंगे और हमें उस भविष्य में भागीदार होने पर गर्व है।''

'इंडो-नेपाल व्यापार मेला' नई दिल्ली में 20 से 22 फरवरी तक पीएचडी चैंबर भवन में लगेगा

एजेंसी

नई दिल्ली। 'इंडो-नेपाल व्यापार मेला' 20 से 22 फरवरी तक नई दिल्ली के पीएचडी चैंबर भवन में लगाया जायेगा। व्यापार मेला के इस दूसरे संस्करण में 65 प्रदर्शनी स्टॉल होंगे। यह ऐतिहासिक द्विपक्षीय मेला भारत-नेपाल आर्थिक कूटनीति को और सुदृढ़ करते हुए दीर्घकालीन क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा।

प्रेस क्लब में एक प्रेस कांफ्रेंस में एवरेस्ट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (ईसीसीआई) के अध्यक्ष युवराज बराल ने इंडो-नेपाल व्यापार मेला के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस व्यापार मेला के उद्घाटन सत्र में भारत में नेपाल के राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा, मुख्य अतिथि भारत सरकार के पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) के अध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति रहेगी। युवराज बराल ने बताया कि इंडो-नेपाल ट्रेड फेस्टिवल को व्यापार, पर्यटन, संस्कृति और नवाचार के माध्यम से द्विपक्षीय

सहयोग को सुदृढ़ करने वाले एक परिवर्तनकारी मंच के रूप में परिकल्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सार्थक साझेदारी विकसित करने, निवेश के अवसरों का विस्तार करने और दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने में यह महोत्सव सहायक सिद्ध होगा। एवरेस्ट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के महासचिव डॉ. मोहन कार्की ने बताया कि ये व्यापार मेला भारत-नेपाल के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग, पर्यटन एकीकरण, सांस्कृतिक आदान-प्रदान तथा निवेश साझेदारी को सुदृढ़ करने वाले एक प्रमुख मंच के रूप में स्थापित हो चुका है। इस वर्ष के 'इंडो-नेपाल व्यापार मेला' में जलविद्युत एवं ऊर्जा साझेदारी, सीमा-पार व्यापार एवं कनेक्टिविटी, रामायण और बौद्ध सर्किट सहित पर्यटन एकीकरण, बैंकिंग, फिनटेक एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था सहयोग, मीडिया एवं सांस्कृतिक कूटनीति, युवा सहभागिता, शिक्षा एवं नवाचार साझेदारी, स्टार्टअप इकोसिस्टम तथा इंडो-नेपाल सहयोग 'विजन 2030' जैसे विषयों पर 10 से ज्यादा उच्चस्तरीय सत्र और नीतिगत संवाद आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 60 से अधिक विशेषज्ञ भाग लेंगे।

क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस का आईपीओ 23 फरवरी को खुलेगा, प्राइस बैंड 1,000-1,053 रुपये प्रति शेयर

एजेंसी

नई दिल्ली/मुंबई। क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 23 फरवरी को खुलेगा। इसमें निवेश के लिए 25 फरवरी तक बोली लगा सकते हैं। कंपनी ने इसके लिए मूल्?य का दायरा (प्राइस बैंड) 1,000-1,053 रुपये तय किया है। क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने जारी बयान में बताया कि उसका आईपीओ सार्वजनिक बिक्री के लिए 23 फरवरी को खुलकर 25 फरवरी को बंद होगा, जबकि एंकर निवेशक 20 फरवरी को इसमें निवेश करने के लिए बोली लगा सकेंगे। इसके लिए मूल्य का दायरा (प्राइस बैंड) 1,000-1,053 रुपये तय गया किया है। वाणिज्यिक और औद्योगिक (सीएंडआई) नवीकरणीय ऊर्जा प्रदाता कंपनी क्लीन मैक्स ने कहा कि 1 रुपये फेस वैल्यू वाले प्रस्तावित आईपीओ में 1,200 करोड़ रुपये तक के शेयरों का ताजा निर्गम और प्रवर्तकों और

एक निवेशक शेयरधारक द्वारा 1,900 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री की पेशकश (ओएफएस) शामिल है। निवेशक इसमें कम से कम 14 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 14 इक्विटी शेयर्स के मल्टीपल में बिड कर सकते हैं।

कंपनी की योजना इस आईपीओ के जरिए 3,100 करोड़ रुपये जुटाने की है। क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड इस ताजा इश्यू से मिलने वाली 1,122.6 करोड़ रुपये की रकम का इस्तेमाल कंपनी और/या उनकी सब्सिडियरी कंपनियों के सभी या कुछ बकाया उधारों के कुछ हिस्से या पूरे रीपेमेंट और/या प्री-पेमेंट और आम कॉर्पोरेट कामों के लिए करेगी। उल्लेखनीय है कि क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड एक वाणिज्यिक और औद्योगिक नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है, जिसकी स्थापना वर्ष 2010 में मुंबई भारत में हुई थी। इस कंपनी की स्थापना कुलदीप जैन, प्रताप जैन और निधि जैन ने कॉर्पोरेट प्रमोटर बीजीटीएफ वन होल्डिंग्स (डीआईएफसी) लिमिटेड और केएमपीआईएनसी एलएलपी के साथ मिलकर की थी।

सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए 'परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा' को बढ़ावा देने को सुविधा शिविरों का उद्घाटन

एजेंसी

नई दिल्ली। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए 'परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा' को बढ़ावा देने के लिए सुविधा शिविरों का उद्घाटन किया। इसके तहत पॉलिसी में 10-20 लाख रुपये तक का लचीले सह-भुगतान विकल्प और व्यापक अस्पताल नेटवर्क में भर्ती होने पर कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध है। वित्त मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव एम. नागराजू ने नई दिल्ली स्थित डीएफएस परिसर में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा आयोजित सुविधा शिविरों का उद्घाटन किया। मंत्रालय के मुताकिबक भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा इस प्रकार के सुविधा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा 14 जनवरी, 2026 को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना शुरू की गई है।

यह कैशलेस सुविधाएं, आधुनिक उपचार और अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करती है। यह स्वास्थ्य बीमा उत्पाद विशेष रूप से सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिसमें प्रति पॉलिसी अधिकतम छह सदस्य हो सकते हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक यह भारत के भीतर भर्ती होने पर क्षतिपूर्ति-आधारित कवरेज प्रदान करता है, जिसमें 10 लाख रुपये या 20 लाख रुपये के बीमा राशि विकल्प उपलब्ध हैं। उत्पाद में सह-भुगतान घटक होगा, जिससे लाभार्थियों को बीमा कंपनी और ग्राहकों के बीच 70:30 या 50:50 की सह-साझेदारी का विकल्प चुनने की सुविधा मिलेगी। यह उत्पाद लगभग 20,800 तृतीय पक्ष प्रशासक नेटवर्क अस्पतालों और लगभग 5050 बीमाकर्ता नेटवर्क अस्पतालों के माध्यम से नकद रहित अस्पताल में भर्ती की सुविधा प्रदान करता है। मंत्रालय के मुताबिक पॉलिसी की अन्य विस्तृत जानकारी एनआईएसीएल की आधिकारिक वेबसाइट https://www.newindia.co.in/health-insurance/paripoorna-ayush-bima पर देखी जा सकती है। यह वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा योजना सभी सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए खुदरा उत्पाद के रूप में उपलब्ध है, और अधिकतम सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए इस पर कोई जीएसटी नहीं है। मौजूदा लाभों के पूरक के रूप में डिजाइन की गई यह उन्नत पॉलिसी देशभर में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक अधिक लचीलापन और विस्तारित पहुंच प्रदान करते हुए, एक सहज अनुभव प्रदान करेगी, जिससे सभी सीजीएचएस लाभार्थियों को आसानी और आत्मविश्वास के साथ अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होगी।

पेप्सिको का पसंदीदा आलू चिप्स ब्रांड 'लेज' मार्च से नई पैकिंग में नजर आएगा

एजेंसी

नई दिल्ली। पेप्सिको का पसंदीदा आलू चिप्स ब्रांड लेज मार्च से भारत में अपनी नई ब्रांड पहचान यानी नई 'पैकिंग' में नजर आएगा। लेज का ये नया अवतार ब्रांड एंबेसडर रणबीर कपूर के साथ इसके नए 'लेज के लिए कुछ भी' कैंपेन के जरिए स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। कंपनी ने जारी एक बयान में बताया कि पसंदीदा पोटैटो चिप्स ब्रांड लेज भारत में अपनी नई ब्रांड पहचान लॉन्च करेगा। पेप्सिको के अनुसार नए 'लोगो' (पहचान चिह्न) वाले लेज के नए पैकेट मार्च के पहले हफ्ते से पूरे भारत में उपलब्ध होंगे। ये कंपनी के करीब 100 साल के इतिहास में सबसे बड़े वैश्विक ब्रांड नवीनीकरण अभियान का हिस्सा है। यह बदलाव न केवल भारत में बल्कि, दुनियाभर के बाजारों में एक साथ किया जा रहा है, ताकि ब्रांड की वैश्विक पहचान को एकरूपता दी जा सके। पेप्सिको इंडिया में खाद्य उत्पादों की मुख्य विपणन अधिकारी (सीएमओ) साक्षी वर्मा मेनन ने कहा कि खेत से पैकेट तक की यात्रा को अधिक स्पष्ट तरीके से दर्शाते हुए हम लेज के विकास में टिकाऊपन तथा गुणवत्ता को केंद्र में रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई पहचान को इसके ब्रांड एंबेसडर रणबीर कपूर के साथ 'लेज के लिए कुछ भी' कैंपेन के जरिए स्क्रीन पर दिखाया जाएगा।

सम्राट चौधरी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में बिहार पवेलियन का किया उद्घाटन, 468 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर

एजेंसी

नई दिल्ली। बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट एंड एक्सपो 2026 के दौरान बिहार राज्य पवेलियन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने की। इस मौके पर बिहार सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी सिंह, उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल तथा राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विशेषज्ञ मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि बिहार सरकार राज्य को उभरते हुए

प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। इन पहलों के तहत बिहार एआई मिशन के अंतर्गत मेगा एआई कोर ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना, उद्योग एवं शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी, निवेशकों के साथ निवेश समझौते तथा बिहार जीसीसी नीति 2026 और बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 का शुभारंभ शामिल है। इसके अलावा आईआईटी पटना में अत्याधुनिक रिसर्च पार्क स्थापित करने की योजना भी बनाई गई है, जिससे अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी विकास को नई गति मिलेगी। समिट के दौरान बिहार सरकार ने प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों और आईआईटी पटना के साथ कुल 468 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इनमें बिहार एआई उत्कृष्टता केंद्र (एआई-कोड) की स्थापना के लिए 60 करोड़ रुपये तथा आईआईटी पटना में रिसर्च पार्क के निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। इस परियोजना में टाइगर एनालिटिक्स उद्योग भागीदार तथा आईआईटी पटना शैक्षणिक भागीदार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके अतिरिक्त बिहार जीसीसी नीति 2026 और बिहार आईटी नीति 2024 के अंतर्गत रेड साइबर, ग्रोक्यूआर और सीआईपीएल जैसी प्रमुख आईटी और जीसीसी कंपनियों के साथ भी निवेश और तकनीकी सहयोग के समझौते किए गए हैं। इन समझौतों का उद्देश्य राज्य में निवेश को आकर्षित करना, स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना, नवाचार को बढ़ावा देना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। बिहार सरकार का मानना है कि इन पहलों से राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सेमीकंडक्टर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेजी से विकास होगा।

सीतारमण और नॉर्वे के वित्त मंत्री स्टोलटेनबर्ग ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर की चर्चा

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओस्लो में नॉर्वे के वित्त मंत्री जेन्स स्टोलटेनबर्ग से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री ने स्टोलटेनबर्ग के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, विशेष रूप से सौर ऊर्जा, दुर्लभ खनिज प्रसंस्करण और 'कार्बन कैप्चर' एवं भंडारण में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। वित्त मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने इस मुलाकात के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, विशेष रूप से सौर ऊर्जा, दुर्लभ खनिज प्रसंस्करण और 'कार्बन कैप्चर' एवं भंडारण क्षेत्र में मिलकर काम करने पर चर्चा की।'' इसके साथ ही दोनों नेताओं ने विशेष रूप से समुद्री अर्थव्यवस्था और हरित अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) का लाभ उठाने की

दिशा में काम करने पर सहमति जताई।ओस्लो में निर्मला सीतारमण के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक में नॉर्वे के वित्त मंत्री जेन्स स्टोलटेनबर्ग स्टोलटेनबर्ग ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि निवेश और विकास के लिए कई अवसर प्रदान करती है। स्टोलटेनबर्ग ने सीतारमण को यह भी बताया कि नॉर्वे इस वर्ष के अंत में होने वाली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई की कि इससे भारत और नॉर्वे के बीच सहयोग और बढ़ेगा।

मारुति ने शुरू की ई-विटारा की बिक्री

एजेंसी

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी यात्री वाहन निर्माता मारुति सुजुकी ने अपने एसयूवी विटारा के इलेक्ट्रिक संस्करण ई-विटारा की घरेलू बाजार में बिक्री शुरू कर दी। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि ग्राहक नेक्सा शोरूम पर जाकर या नेक्सा की वेबसाइट पर 21,000 रुपये का

शुरुआती भुगतान करके ई-विटारा की बुकिंग करा सकते हैं। ई-विटारा के 49 किलोवाट आवर मॉडल की बैटरी-एज-ए-सर्विस विकल्प के साथ कीमत 10.99 लाख रुपये है। इसमें रोड टैक्स, बीमा, टीसीएस और अन्य सरकारी कर तथा शुल्क शामिल नहीं हैं। बैटरी के लिए 3.99 रुपये प्रति किलोमीटर की समान किस्तों का विकल्प है। कंपनी एक साल बाद 60 प्रतिशत कीमत पर वाहन वापस खरीदने, बैटरी पर आठ साल और एसयूवी पर तीन साल की वारंटी दे रही है। वाहन पर पांच साल की अतिरिक्त गारंटी भी खरीदी जा सकती है। कंपनी ई-विटारा के साथ घर पर चार्जिंग की सुविधा इंस्टाल करेगी और होम चार्जर भी देगी।

मप्र की जीडीपी में 11.14 प्रतिशत वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय बढ़कर हुई 1,69,050 रुपये हुई

एजेंसी

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया। सर्वेक्षण के अनुसार, मध्य प्रदेश की जीडीपी में 11.14 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जबकि प्रति व्यक्ति आय बढ़कर एक लाख 69 हजार 50 रुपये हो गई है। उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने विधानसभा में आर्थिक बजट पेश करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश ने दूरदर्शी आर्थिक नीतियों के साथ संतुलित और समावेशी विकास का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में प्रस्तुत आँकड़ों से जाहिर है कि मध्य प्रदेश योजनाबद्ध, संतुलित और परिणामोन्मुख विकास पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का विकास योजनाबद्ध, संतुलित और समावेशी रणनीति पर आधारित है। कृषि से उद्योग, सेवा से सामाजिक क्षेत्र और वित्तीय अनुशासन से सुशासन तक प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर प्रगति हुई है। उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत को विश्व की मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने मध्यप्रदेश पूरी क्षमता के साथ तैयार है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने आर्थिक समृद्धि के जो कदम उठाये हैं, उनके परिणाम मिलना शुरू हो गये हैं। उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने विधानसभा में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2025-26 अग्रिम अनुमान में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) प्रचलित भाव पर 16,69,750 करोड़ रूपये आँका गया है, जो वर्ष 2024-25 के 15,02,428 करोड़ रुपये की तुलना में 11.14 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। इसी प्रकार स्थिर (2011-12) भाव पर जीएसडीपी 7,81,911 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो 8.04 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विस्तार केवल मूल्य वृद्धि का परिणाम नहीं, बल्कि वास्तविक उत्पादन और गतिविधियों में वृद्धि का परिणाम है। देवड़ा ने कहा कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2011-12 में प्रचलित भाव पर 38,497 रुपये रही प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2025-26 में बढ़कर 1,69,050 रुपये हो गई है। स्थिर (2011-12) भाव पर यही आय 76,971 रुपये तक पहुँच गई है। उन्होंने कहा कि यह आय स्तर में सुधार का संकेत है, जो जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन को रेखांकित करता है। देवड़ा ने वर्ष 2025-26 में प्रचलित भाव पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 43.09 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का 19.79 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र का 37.12 प्रतिशत रहा। स्थिर भाव पर यह संरचना क्रमशः 33.54 प्रतिशत, 26.18 प्रतिशत और 40.28 प्रतिशत रही। इससे जाहिर है कि कृषि आधारित आधार को मजबूती देते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में भी संतुलित विस्तार हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, प्राथमिक क्षेत्र में वर्ष 2025-26 में कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन 6,79,817 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष के 6,33,532 करोड़ रुपये की तुलना में 7.31 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। इस क्षेत्र में फसलें 30.17 प्रतिशत भागीदारी के साथ प्रमुख घटक रहीं। पशुधन, वानिकी, मत्स्य एवं जलीय कृषि तथा खनन एवं उत्खनन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती कार हमला, 11 सुरक्षाकर्मियों की मौत

एजेंसी

क्वेटा। पाकिस्तान के अशांत उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती कार बम हमले में कम से कम 11 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई। यह हमला बाजौर जिला में अफगान सीमा के नजदीक एक संयुक्त चेकपोस्ट पर हुआ। लगातार बढ़ती हिंसा ने सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक विस्फोटकों से भरे वाहन को सुरक्षा चौकी से टकराया गया, जिससे चौकी को भारी नुकसान पहुंचा। यह पोस्ट फ्रंटियर कॉर्प्स द्वारा संचालित थी। अफगानिस्तान की समाचार ने बताया कि धमाका इतना शक्तिशाली था कि इमारत मलबे में तब्दील हो गई। आसपास के घर भी प्रभावित हुए। एक बच्चे की मौत और कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। स्थानीय लोगों ने अंधेरे में राहत-बचाव का प्रयास किया।हाल के महीनों में क्षेत्र में उग्रवादी हमलों में बढ़ोतरी देखी गई है। बन्नू जिले में पुलिस स्टेशन के पास हुए एक अन्य विस्फोट में दो लोगों की जान गई और कई घायल हुए। यह जानकारी पाकिस्तानी दैनिक डॉन ने दी। सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि देश में हिंसक घटनाओं का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में सैकड़ों आतंकी हमले दर्ज किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए या घायल हुए।

ओम बिरला ने तारिक रहमान से मुलाकात कर भारत आने का दिया न्योता

ढाका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यहां बंगलादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद उनसे मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से भारत आने का निमंत्रण दिया। श्री रहमान को प्रधानमंत्री का पद संभालने पर बधाई देते हुए श्री बिरला ने भारत की ओर से सद्भावना और समर्थन व्यक्त किया। श्री बिरला ने श्री रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने बाद में श्री रहमान से मुलाकात कर उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भारत यात्रा पर आने का औपचारिक निमंत्रण सौंपा। लोकसभा अध्यक्ष ने दोनों देशों के बीच साझा आकांक्षाओं और ऐतिहासिक संबंधों पर जोर देते हुए कहा, 'भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी राष्ट्र के निर्माण के लिए बंगलादेश के प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है।' भारत में बंगलादेश के उच्चायुक्त रियाज़ हमीदुल्लाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'माननीय अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया। दोनों नेताओं ने मिलकर दोनों देशों की जनता की भलाई के लिए काम करने की आशा व्यक्त की। ' राजनयिक सूत्रों के अनुसार श्री बिरला की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग मजबूत होने की उम्मीद है। भारत और बंगलादेश गहरे सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं, जो 1971 में बंगलादेश के मुक्ति संग्राम के बाद से काफी मजबूत हुए हैं।

अमेरिकी नागरिक अधिकार नेता जेसी जैक्सन का 84 साल की उम्र में निधन

वॉशिंगटन। अमेरिका के नागरिक अधिकार नेता, मार्टिन लूथर किंग के सहयोगी और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जेसी जैक्सन का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जैक्सन परिवार के बयान में कहा गया, ' श्री जैक्सन मंगलवार सुबह अपने परिवार के बीच शांति से गुज़र गये। न्याय, समानता और मानवाधिकारों के लिए उनके पक्के इरादे ने आज़ादी और सम्मान के लिए दुनिया भर में चल रहे आंदोलन को हिला दिया। ' श्री जैक्सन एक जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। उन्होंने 1984 और 1988 में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए दो बार चुनाव लड़ा था। आठ अक्टूबर 1941 को ग्रीनविल, दक्षिण कैरोलिना में जन्मे जैक्सन कम उम्र में ही राजनीति में शामिल हो गये थे। वह 1960 के दशक में मार्टिन लूथर किंग के सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के लीडर के तौर पर मशहूर हुए। जब किंग की 1968 में मेम्फिस, टेनेसी में हत्या हुई, तो वह उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने 1971 में ऑपरेशन पुश, और 1983 में नेशनल रेनबो कोएलिशन सहित दो सामाजिक न्याय संगठन शुरू किये। जैक्सन बाद की ज़िंदगी में भी एक मानवाधिकार कार्यकर्ता बने रहे। उन्होंने अमेरिका और विदेशों में वंचित समूहों के लिए नागरिक अधिकारों की मांग लगातार जारी रखी।

जून 2025 के हमलों का जिक्र कर बोले ट्रंप, जिनेवा में ईरान से समझदारी की उम्मीद

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जून 2025 में हुए हमलों का ज़िक्र करते हुए कहा है कि जिनेवा में होने वाली बैठक में ईरान से 'समझदारी' की उम्मीद है। श्री ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वह अमेरिका और ईरान के बीच जिनेवा में होने वाली उच्च स्तरीय परमाणु वार्ता में 'अप्रत्यक्ष रूप से' शामिल रहेंगे।उन्होंने फोर्दो, इस्फहान और नतांज पर हुए अमेरिकी हमलों का उल्लेख करते हुए ईरान से बातचीत के दौरान 'तर्कसंगत' रुख अपनाने की अपील की। श्री ट्रंप ने एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'मैं इन वार्ताओं में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहूंगा और ये बेहद महत्वपूर्ण होंगी।

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से नेपाल के विदेशमंत्री ने की मुलाकात

एजेंसी

काठमांडू। नेपाल के विदेशमंत्री बालानंद शर्मा ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से शिष्टाचार मुलाकात की है। शर्मा ने उन्हें बधाई दी और नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की ओर से शुभकामना संदेश सौंपा। संदेश में रहमान की चुनावी जीत की सराहना करते हुए आपसी सम्मान, साझा प्राथमिकताओं और साझेदारी के आधार पर नेपाल-बांग्लादेश संबंधों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई गईढाका स्थित नेपाली राजदूतावास के तरफ से आज जारी एक बयान में कहा गया है कि नेपाल के विदेशमंत्री शर्मा ने 12 फरवरी को हुए राष्ट्रीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को निर्णायक जीत दिलाने के लिए भी

रहमान को बधाई दी और बांग्लादेश में शांतिपूर्ण व सफल लोकतांत्रिक सत्ता हस्तांतरण की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री रहमान ने शपथ ग्रहण समारोह में शर्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि यह बांग्लादेश के प्रति नेपाल सरकार और नेपाली जनता की एकजुटता तथा सद्भावना को दर्शाता है।

बयान में दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराने की जानकारी दी गई है। रहमान ने नेपाल में आगामी पांच मार्च को होने जा रहे संसदीय चुनाव के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नेपाल में भी आम चुनाव के जरिए जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा। बैठक से पहले विदेशमंत्री शर्मा ने बांग्लादेश के नवनियुक्त प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। अपनी यात्रा के दौरान शर्मा ने विपक्ष के नेता डॉ. शफीकुर रहमान तथा जमात-ए-इस्लामी के अमीर से भी मुलाकात कर द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की। विदेशमंत्री की बांग्लादेश यात्रा 19 फरवरी तक चलेगी।

हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान का अस्थायी प्रतिबंध, परमाणु वार्ताओं के बीच शक्ति प्रदर्शन

एजेंसी

जेनेवा/तेहरान। ईरान ने लाइव-फायर सैन्य अभ्यास के चलते रणनीतिक रूप से अहम हॉर्मुज जलडमरूमध्य को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब ईरानी प्रतिनिधि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने विवादित परमाणु कार्यक्रम को लेकर जेनेवा में अप्रत्यक्ष वार्ताओं में शामिल हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक, अभ्यास के दौरान जलडमरूमध्य की दिशा में मिसाइलें दागी गईं और 'समुद्री सुरक्षा' कारणों से मार्ग को कुछ घंटों के लिए बंद रखा गया। यह पहला अवसर बताया जा रहा है जब हालिया तनाव के दौर में ईरान ने इस अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पर औपचारिक अस्थायी रोक की घोषणा की है। इसी मार्ग से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है।

अर्ध-सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी, जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के करीबी मानी जाती है, ने दावा किया कि देश के भीतर और तटीय इलाकों से दागी गई मिसाइलों ने अपने लक्ष्य साधे। विश्लेषकों का मानना है कि सैन्य अभ्यास और कूटनीतिक वार्ताएं समानांतर चलने से क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। इसे पश्चिम एशिया में जारी टकराव के बीच एक सख्त संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है, हालांकि वार्ता जारी रहने से कूटनीतिक समाधान की संभावना बनी हुई है।

उत्तर कोरिया में उत्तराधिकार की जंग तेज, किम जोंग उन ने 13 वर्षीय बेटी को सौंपी कमान

एजेंसी

सियोल। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी (NIS) ने दावा किया है कि उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी 13 वर्षीय बेटी किम जू ए को अपना उत्तराधिकारी लगभग तय कर लिया है। फरवरी के अंत में होने वाले बड़े राजनीतिक सम्मेलन में उसे पार्टी का 'प्रथम सचिव' जैसा महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। किम जू ए पिछले दो वर्षों से अपने पिता के साथ मिसाइल परीक्षणों, सैन्य परेडों और हाल ही में बीजिंग दौरे पर देखी गई हैं। सरकारी मीडिया द्वारा उनके लिए 'सम्मानित' शब्द का प्रयोग इस बात की पुष्टि करता है कि उन्हें देश के सर्वोच्च पद के लिए तैयार किया जा रहा है। उत्तराधिकारी के रूप में बेटी का नाम सामने आने से किम परिवार के भीतर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। वर्तमान में किम जोंग उन की बहन, किम यो जोंग को देश की दूसरी सबसे शक्तिशाली हस्ती माना जाता है, जिन्हें सेना और वर्कर्स पार्टी का मजबूत राजनीतिक समर्थन प्राप्त है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि किम जू ए को आधिकारिक तौर पर गद्दी सौंपी जाती है, तो आने वाले समय में

बुआ और भतीजी के बीच वर्चस्व की भीषण लड़ाई देखने को मिल सकती है। प्योंगयांग के कुमसुसान पैलेस की हालिया यात्रा को इस उत्तराधिकार को प्रतीकात्मक मंजूरी दिलाने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। 1948 से उत्तर कोरिया पर किम परिवार के पुरुष सदस्यों का शासन रहा है, लेकिन किम जोंग उन इस परंपरा को बदलकर अपनी बेटी को कमान सौंपने की राह पर हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, किम खुद 26 वर्ष की उम्र में अचानक सत्ता में आए थे, इसलिए वे अपनी बेटी को बहुत कम उम्र से ही सार्वजनिक जीवन और सैन्य मामलों में शामिल कर रहे हैं। हालांकि, किम जोंग उन की उम्र अभी कम है, इसलिए दक्षिण कोरियाई एजेंसियां इस बात पर कड़ी नजर रख रही हैं कि क्या आगामी पार्टी कांग्रेस में हजारों प्रतिनिधियों के सामने उत्तराधिकारी के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाता है या नहीं।

इस्लामिक गणराज्य का तख्तापलट नहीं कर पाएगा अमेरिका : खामेनेई

एजेंसी

तेहरान। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका इस्लामिक गणराज्य के तख्तापलट में कभी कामयाब नहीं होगा और अगर वह ऐसा करने की कोशिश करता है तो 'दुनिया की सबसे ताकतवर सेना' को भी गहरे आघात पहुंच सकते हैं। श्री खामेनेई ने पूर्वी अज़रबेजान के लोगों के साथ एक बैठक में कहा, 'अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने एक हालिया बयान में कहा है कि अमेरिका 47 साल तक इस्लामिक गणराज्य को हराने में नाकाम रहा है। उन्होंने अपने ही लोगों से इसकी शिकायत की। यह एक अच्छा इकबालिया बयान है। मैं कहता हूं कि आप (डोनाल्ड ट्रंप) भी यह नहीं कर पाएंगे। ' श्री खामेनेई का यह बयान ऐसे समय में आया है जब श्री ट्रंप ने कहा था कि ईरान में तख्तापलट सबसे अच्छी चीज़ हो सकती है। श्री खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति के उस बयान का भी ज़िक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी सेना दुनिया में सबसे ताकतवर है। उन्होंने कहा, 'दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को भी कभी ऐसा जख्म मिल सकता है कि वह उठ न सके। वे कहते रहते हैं कि हमने ईरान की ओर युद्धपोत भेज दिया है। युद्धपोत खतरनाक तो है, लेकिन उससे भी खतरनाक वह हथियार है जो उस युद्धपोत को समंदर की तह में पहुंचा सकता है।' उल्लेखनीय है कि अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता का दूसरा दौर भी जारी रहा। इस बीच, श्री खामेनेई ने कहा कि अमेरिका की धमकियां ईरान को काबू करने की कोशिश का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका की सत्ता पर काबिज़ भ्रष्ट नेताओं के आगे नहीं झुकेगा। श्री खामेनेई ने कहा, 'वे कहते हैं कि परमाणु ऊर्जा पर बातचीत करो, और बातचीत का नतीजा यह रहेगा कि तुम्हारे पास परमाणु ऊर्जा नहीं बचेगी। अगर बातचीत होनी ही है तो पहले से उसका नतीजा निर्धारित कर लेना गलत और बेवकूफाना है। ' श्री खामेनेई ने इसी भाषण में कहा कि देश में आर्थिक तंगी के खिलाफ जनवरी में हुए प्रदर्शनों के दौरान मारे गये लोगों को शहीद माना गया है। उन्होंने कहा, 'खून बहा है। हम दुखी हैं। मैं कहता हूं कि हम बहे हुए खून के लिए शोकाकुल हैं। 'उल्लेखनीय है कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जनवरी के प्रदर्शनों में 3,117 लोगों की मौत हुई है, जबकि गैर-सरकारी संगठनों के अनुसार यह आंकड़ा इससे काफी बड़ा है। श्री खामेनेई ने यह भी कहा कि मरने वाले सभी लोग शहीद की श्रेणी में नहीं आते। इनमें से कुछ भ्रष्ट तत्व और भड़काऊ लोग थे, जबकि बाकियों ने विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में कोई भूमिका नहीं निभाई। उन्होंने प्रदर्शनों में मरने वालों को तीन श्रेणियों में बांटा। उन्होंने कहा कि ईरान के मरने वाले शहीदों का दायरा बड़ा है, लेकिन जिन लोगों ने दुश्मन से पैसे और हथियार लिये, वे 'रिंगलीडर' हैं और उन्हें शहीद नहीं माना जा सकता।

किसी भी देश पर चीन से रिश्ता तोड़ने का दबाव नहीं बनाएगा अमेरिका: मार्को रुबियो

एजेंसी

ढाका। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के अध्यक्ष तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 49 मंत्रियों ने भी शपथ ली। संसद भवन परिसर के साउथ प्लाजा में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने तारिक रहमान और उनके नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी। रहमान की 49 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में 25 मंत्री और 24 राज्यमंत्री शामिल हैं। बांग्लादेश के इतिहास में लंबे समय की परंपरा तोड़ते हुए नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन के बजाय संसद भवन परिसर के साउथ प्लाजा में आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू, भूटान के प्रधानमंत्री दाशो त्सेरिंग टोबगे, पाकिस्तान के नियोजन

एवं विकास मंत्री अहसान इकबाल चौधरी, नेपाल के विदेश मंत्री बालानंद शर्मा, श्रीलंका के स्वास्थ्य एवं जनसंपर्क मंत्री डॉ. नलिंदा जयतिस्सा सहित विभिन्न देशों के नेता शामिल हुए। समारोह में मुख्य न्यायाधीश, अंतरिम सरकार के पूर्व मुख्य सलाहकार प्रो. मुहम्मद यूनुस एवं उनके सलाहकार परिषद, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सांसद, राजनीतिक नेता, तीनों सेनाओं के प्रमुख, राजनयिक मिशनों के सदस्य, वरिष्ठ पत्रकार तथा उच्च सिविल एवं सैन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। तारिक रहमान की पत्नी डॉ. जुबैदा रहमान, उनकी बेटी बैरिस्टर जाइमा रहमान तथा अन्य परिजन भी समारोह में मौजूद रहे। समारोह में करीब 1200 मेहमान उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत पवित्र कुरान की तिलावत से हुई। तारिक रहमान ने सबसे पहले राष्ट्रीय संविधान की रक्षा, संरक्षण एवं राज्य की संप्रभुता की रक्षा करने की शपथ ली।

कैबिनेट सचिव डॉ. नसीमुल गनी ने शपथ समारोह का संचालन किया। बांग्लादेश में हालिया संपन्न संसदीय चुनाव में बीएनपी को लगभग 50 प्रतिशत मत मिले। बीएनपी ने इस चुनाव में दो तिहाई बहुमत से सत्ता हासिल की है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी को 300 में से 209 सीटें मिली हैं।

रूस से ले जाए गए 2,000 यूक्रेनी बच्चे वापस लाए गए : जेलेंस्की

एजेंसी

कीव। वोलोदिमिर जेलेंस्की ने घोषणा की है कि रूस ले जाए गए लगभग 2,000 यूक्रेनी बच्चों को वापस उनके घर लाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास उनके 'ब्रिंग किड्स बैक' अभियान के तहत लगातार चल रही मानवीय पहल का हिस्सा है।जेलेंस्की के अनुसार, बच्चों

की वापसी सरकार, नागरिक संगठनों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के समन्वित प्रयासों से संभव हो सकी। उन्होंने इस सहयोग के लिए सभी भागीदारों का आभार जताते हुए कहा कि यह लड़ाई बच्चों और देश के भविष्य से जुड़ी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यह भी माना कि चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। उनके मुताबिक, कई यूक्रेनी बच्चे अब भी रूस में हैं और उन्हें वापस लाने के प्रयास जारी रहेंगे। जेलेंस्की ने दोहराया कि जब तक हर यूक्रेनी बच्चा सुरक्षित घर नहीं लौट आता, तब तक अभियान जारी रहेगा। यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव के बीच बच्चों की सुरक्षित वापसी को मानवीय मुद्दा बताया जा रहा है।

वायु प्रदूषण बढ़ने से काठमांडू इस समय वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे प्रदूषित शहर

एजेंसी

काठमांडू। काठमांडू में वायु प्रदूषण में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। काठमांडू इस समय वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। भारत की दिल्ली 229 एक्यूआई के साथ पहले स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान का लाहौर 203 एक्यूआई के साथ दूसरे स्थान पर है। काठमांडू में मंगलवार दोपहर तक वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 191 पहुंच गया, जो 178 था। यह स्तर सभी के लिए अस्वस्थ श्रेणी में आता है, जिससे विशेष रूप से बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों तथा श्वसन या हृदय संबंधी रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य जोखिम बढ़ गए हैं। एक्यूआई मानकों के अनुसार 0-50 अच्छा (हरा), 51-100 सतर्कता आवश्यक (पीला), 101-150 संवेदनशील समूहों के लिए अस्वस्थ, 151-200 सभी के लिए

अस्वस्थ, 201-300 अत्यंत अस्वस्थ और 300 से ऊपर खतरनाक माना जाता है।पर्यावरण विभाग के महानिदेशक ज्ञानराज सुवेदी ने चेतावनी दी कि यदि आने वाले दिनों में वर्षा नहीं हुई तो प्रदूषण और बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि बारिश हवा में मौजूद धूल और कणों को बैठाने में मदद करती है, इसलिए लंबे समय तक शुष्क मौसम रहने से प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। सुवेदी ने संबंधित निकायों को टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने की सलाह भी दी। उन्होंने वाहनों की तेज़ वृद्धि, डीज़ल और पेट्रोल से निकलने वाला धुआं, सड़क व अवसंरचना परियोजनाओं से उठने वाली धूल, वनाग्नि तथा लंबे समय तक शुष्क मौसम को वायु प्रदूषण बढ़ने के प्रमुख कारण बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय पर कदम नहीं उठाए गए, तो स्थिति और जटिल हो सकती है।

काठमांडू वायु गुणवत्ता प्रबंधन कार्ययोजना-2076 के तहत नेपाल सरकार एक्यूआई 300 से अधिक होने पर इसे आपदा की स्थिति मानती है। इसके अंतर्गत खुले में कचरा जलाने पर रोक, झाड़ू और वैक्यूम क्लीनर जैसी सड़क सफाई मशीनों के उपयोग में वृद्धि तथा बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और रोगियों के लिए सार्वजनिक चेतावनी जारी करने जैसे उपाय शामिल हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के अनुसार वायु, जल, मृदा, ध्वनि, विद्युतचुंबकीय तरंगों, रेडियोधर्मी उत्सर्जन और खतरनाक रसायनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय मानकों का निर्माण और क्रियान्वयन अनिवार्य है। इसके साथ ही प्रमुख शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों और उच्च-जोखिम वाले इलाकों में निगरानी केंद्र स्थापित कर वायु, जल और ध्वनि की गुणवत्ता का मानचित्रण करने का प्रावधान भी किया गया है।

हंगरी, अमेरिका ने परमाणु सहयोग समझौते पर किये हस्ताक्षर

एजेंसी

बुडापेस्ट। हंगरी और अमेरिका ने नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर लिये हैं। यह समझौता अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो की बुडापेस्ट यात्रा के दौरान संपन्न हुआ। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान ने कहा कि यह समझौता तथा अमेरिकी प्रशासन द्वारा प्रतिबंधों से संबंधित दी गयी छूट, दोनों मिलकर हंगरी की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेंगे और देश को घरेलू उपभोक्ताओं तथा उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर ऊर्जा उपलब्ध कराने में मदद करेंगे।

उन्होंने कहा कि हंगरी अपने साझेदारों के साथ खुले और पारदर्शी दृष्टिकोण के साथ काम करता है और किसी भी चिंता का समाधान प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से किया जा सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो ने

कहा कि यह परमाणु ऊर्जा समझौता नवंबर में व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री ऑर्बान के बीच हुई बैठक में हुई चर्चाओं का परिणाम है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि अमेरिकी सरकार ने हंगरी को प्रभावित करने वाले कुछ प्रतिबंधात्मक उपायों को निलंबित कर दिया है, जिससे द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

यूएस ने 24 घंटे में पश्चिम एशिया भेजे 50 से ज्यादा लड़ाकू विमान

एजेंसी

वाशिंगटन। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव गहराता जा रहा है। पहले खबर आई कि अमेरिका ने अपने दो युद्धपोत पश्चिम एशिया में तैनात किए हैं। जिसके बाद आशंका हुई कि अमेरिका, ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अब खबर आई है कि अमेरिका ने बीते 24 घंटे में 50 से ज्यादा लड़ाकू विमान पश्चिम एशिया भेजे हैं। इसे अमेरिका द्वारा ईरान के आसपास अपनी नौसैन्य और वायु सेना की तैनाती बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी सेना को धमकी दी है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना पर भी ऐसा हमला होगा कि वे दोबारा उठ नहीं पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका सेना के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच जिनेवा में हो रही बातचीत में प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होनी है। बीते हफ्ते ही अमेरिका ने अपने सबसे बड़े युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को पश्चिम एशिया में तैनात किया है। साथ ही यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही पश्चिम एशिया में तैनात है। अब 50 से ज्यादा अतिरिक्त लड़ाकू विमान भेजने को अमेरिका द्वारा ईरान पर दबाव बनाने के तौर पर देखा जा रहा है।

अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों में जमीनी स्तर पर कुछ नहीं बदला : विशेषज्ञ

एजेंसी

वॉशिंगटन। पिछले एक साल में अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों की तस्वीर भले ही बेहतर दिख रही हो और दोनों देशों के बीच ऊंचे स्तर पर बातचीत भी बढ़ी हो, लेकिन असल में रिश्तों की बुनियाद में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। दक्षिण एशिया की विशेषज्ञ अपर्णा पांडे ने यह बात कही। उनका कहना है कि अभी तक ज्यादातर बदलाव प्रतीकात्मक हैं, ज़मीन पर न तो आर्थिक और न ही सैन्य स्तर पर पाकिस्तान को खास फायदा मिला है। पाकिस्तान इस हफ्ते वॉशिंगटन में होने वाली 'बोर्ड ऑफ पीस' की पहली बैठक में हिस्सा लेने जा रहा है। इस बैठक को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इसमें शामिल होंगे। इस दौरे को इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ बेहतर होते रिश्तों के सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है। हालांकि मशहूर हडसन इंस्टीट्यूट थिंक-टैंक की अपर्णा पांडे ने कहा कि यह बदलाव स्ट्रक्चरल से ज़्यादा सिंबॉलिक है। उन्होंने कहा, 'यह दौरा मुख्य रूप से बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग में शामिल होने के लिए है। पाकिस्तानी पक्ष शायद पिछले साल से बदले हुए अमेरिकी-पाकिस्तान रिश्तों और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच करीबी, पर्सनल रिश्तों पर जोर देगा। '

इस्लामाबाद से ट्रेड संबंधों पर भी ज़ोर देने की उम्मीद है और वह साइडलाइन पर द्विपक्षीय मीटिंग की मांग कर सकता है। उन्होंने कहा, 'द्विपक्षीय मीटिंग होती है या नहीं, हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा। पांडे ने कहा, 'सिंबॉलिक तौर पर, रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं। हालांकि, असल में, मुझे नहीं लगता कि पिछले एक-डेढ़ साल में पाकिस्तान के अंदर ज्यादा कुछ बदला है। ' गाजा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से मुस्लिम देशों और मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों में भूमिका निभाना चाहता है। अगर पाकिस्तान 'बोर्ड ऑफ पीस' में भाग लेता है या गाजा में कोई जिम्मेदारी निभाता है तो देश के अंदर इसे सकारात्मक रूप से देखा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर पाकिस्तानी सेना को 'फिलिस्तीनी नागरिकों के बजाय इजरायल के समर्थक के तौर पर देखा गया, तो यह अच्छा नहीं लगेगा।' कुल मिलाकर, 'सिंबॉलिक तौर पर यह अच्छा लगेगा,' लेकिन इस्लामाबाद इस बात पर क्लैरिटी चाहेगा कि गाजा में किसी भी इंटरनेशनल स्टेबिलाइजेशन फोर्स के हिस्से के तौर पर उसके सैनिकों से क्या उम्मीद की जाती है। घरेलू राजनीतिक मुद्दों पर, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सदस्य 'सवाल पूछ सकते हैं,' लेकिन 'मुझे नहीं लगता कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कोई सवाल पूछेगा... क्योंकि... यह उनके लिए चिंता का विषय नहीं है। ' पांडे का मानना है कि पाकिस्तान ने अपनी भौगोलिक स्थिति का उपयोग करते हुए अमेरिका के लिए खुद को ईरान, गाजा और फिलिस्तीन से जुड़े मामलों में उपयोगी साबित किया है। पाकिस्तान की नजर में इससे द्विपक्षीय रिश्तों में ठोस लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन फिलहाल जो मिला है, वह सिर्फ प्रतीकात्मक समर्थन और निवेश से जुड़े कुछ ऐलान या संभावित घोषणाएं हैं। ठोस आर्थिक लाभ अभी तक नहीं दिखे हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में इस बात को लेकर नाराजगी भी है। हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यहां तक कह दिया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल टॉयलेट पेपर की तरह किया। सैन्य सहयोग के सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि मौजूदा अमेरिकी प्रशासन पाकिस्तान को उन्नत सैन्य उपकरण आसानी से नहीं देगा। अगर पाकिस्तान को ऐसे हथियार चाहिए, तो उसे खुद खरीदने होंगे। सऊदी अरब या तुर्किये जैसे देश आर्थिक मदद कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की अपनी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह बड़े पैमाने पर महंगे हथियार खरीद सके।

आर्थिक मोर्चे पर उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियां महत्वपूर्ण खनिजों में निवेश कर सकती हैं।

बांस - ऐसी वनस्पति जिसके बहुत से हैं उपयोग

हमारे देश में तेजी से हो रहे सामाजिक-आर्थिक बदलाव से कच्चे माल के रूप में बांस का महत्व न केवल कुटीर उद्योगों में बढ़ा है, बल्कि बड़े उद्योगों में भी इसके महत्व में वृद्धि हुई है। बांस पर आधारित करीब 25,000 उद्योग 2 करोड़ लोगों को रोजगार के असर प्रदान कर रहे हैं जबकि 20 लाख लोग बांस पर आधारित दस्तकारी में लगे हैं।

बांस एक ऐसी वनस्पति है जिसके बहुत से उपयोग हैं। इसके करीब 1,500 उपयोग रिकॉर्ड किए जा चुके हैं जिनमें (a) खाद्य पदार्थ के रूप में (b) लकड़ी के विकल्प के रूप में (c) निर्माण और भवन सामग्री के रूप में (d) हस्तशिल्प वस्तुओं के लिए कच्चे माल की तरह और (e) लुगदी तथा कागज जैसे उपयोग बड़े आम हैं। दुनिया के 80 प्रतिशत बांस के जंगल एशिया में हैं और भारत, चीन तथा म्यांमार में कुल मिलाकर 1.98 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में बांस के वन हैं। भारत दुनिया के सबसे समृद्ध बांस सम्पदा वाले देशों में से एक है और इसके उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है।

भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में बांस का वार्षिक उत्पादन करीब 32.3 करोड़ टन है। भारत बांस उगाने में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। देश के 1.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में बांस की 23 जेनेरा की 136 प्रजातियों की पैदावार होती है। फिर भी विश्व में बांस के व्यापार और वाणिज्य में भारत का हिस्सा सिर्फ चार प्रतिशत ही है। वर्ष 2015-16 और 2016-17 में भारत से बांस और बांस से बने उत्पादों का निर्यात क्रमशः 0.11 करोड़ रुपए और 0.32 करोड़ रुपए का था। बांस उत्पादन के क्षेत्र के विस्तार की व्यापक सम्भावनाएं हैं।

भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार (2011) बांस की 50 प्रतिशत से अधिक प्रजातियाँ पूर्वी भारत में पाई जाती है जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम भी शामिल है। इस क्षेत्र में बांस के बने बर्तन, मछली पकड़ने के जाल, मर्तबान, गुलदस्ते और टोकरियां बनाने की उत्कृष्ट सांस्कृतिक परम्परा रही है। भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना करें तो मिजोरम में बांस के सबसे बड़े जंगल हैं। राज्य के कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक में बांस के जंगल हैं। बांस हमारे जीवन और संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों कला और संगीत में भी किया जाता है। यह एक ऐसा अनोखा पेड़ है जो हमारे दैनिक जीवन में समाया हुआ है। जनजातीय लोगों और वनवासियों का तो अब भी यही आदर्श वाक्य है:-

रोजी-रोटी के लिए बांस और जिन्दगी के लिए बांस!

रोजगार के अवसर बढ़ाने, आमदनी में वृद्धि और ग्रामीण लोगों के भोजन की पौष्टिकता के स्तर में सुधार के लिए बांस बुनियादी आवश्यकता है। यह छोटे और मझोले उद्यमों के क्षेत्र के विस्तार का भी आधार बन सकता है। यह ग्रामीण गरीबी को कम करने और आजीविका सुरक्षा में कारगर भूमिका निभा सकता है।

बांस का पेड़ 4-5 साल में परिपक्व हो जाता है जबकि ठोस लकड़ी वाले किसी पेड़ को परिपक्व होने में करीब 60 साल लगते हैं। लेकिन इमारती लकड़ी वाले पेड़ों से अलग हटकर बांस की पर्यावरण पर बुरा असर डाले बगैर कटाई की जा सकती है। बांस का पेड़ भारी वर्षा या कम वर्षा, दोनों ही तरह की जलवायु में पनप सकता है। हर साल इसके एक पेड़ से 8-10 शाखाएं निकलती हैं। अन्य पेड़ों की तुलना में बांस का पेड़ 35 प्रतिशत अधिक ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ता है और 20 प्रतिशत कार्बन-डाई-ऑक्साइड अवशोषित करता है। बांस की वैज्ञानिक तरीके से खेती करने से वायुमंडल में ऑक्सीजन का उत्सर्जन और कार्बन-डाई-ऑक्साइड का अवशोषण बढ़ाकर वायुमंडल की गुणवत्ता में नाटकीय सुधार लाया जा सकता है।

हमारे देश में तेजी से हो रहे सामाजिक-आर्थिक बदलाव से कच्चे माल के रूप में बांस का महत्व न केवल कुटीर उद्योगों में बढ़ा है, बल्कि बड़े उद्योगों में भी इसके महत्व में वृद्धि हुई है। बांस पर आधारित करीब 25,000 उद्योग 2 करोड़ लोगों को रोजगार के असर प्रदान कर रहे हैं जबकि 20 लाख लोग बांस पर आधारित दस्तकारी में लगे हैं।

बांस के पेड़ के आकर्षक आकार और मजबूती के कारण निर्माण और ढांचे बनाने वाली सामग्री के रूप में इसके उपयोग की व्यापक सम्भावनाएं हैं। बांस की दस्तकारी और बांस पर आधारित संसाधनों का उपयोग करने वालों में लुगदी और कागज उद्योग अग्रणी हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में बांस की खपत से संकेत मिलता है कि (a) 24 प्रतिशत बांस का उपयोग ढांचा खड़ा करने वाली सामग्री के रूप में होता है। (b) 20 प्रतिशत का उपयोग लुगदी और कागज उद्योग में होता है। (c) 19 प्रतिशत हस्तशिल्प बनाने में होता है और (d) 15 प्रतिशत अन्य विविध रूपों में इस्तेमाल किया जाता है।

बांस की रोजगार क्षमता का सारांश

बांस के उपयोग का तरीका

अनुमानित क्षमता/ मात्रा

मात्रा/दिहाडियां (लाख वार्षिक)

वन संवर्घन विज्ञान 25,000 हेक्टेयर 75.00

बांस के बागान लगाना 60 लाख टन 40.00

फसल कटाई 60 लाख टन 100.00

परिवहन/ भंडारण/लदान व उतारना 60 लाख टन 30.00

उत्पादों का निर्माण 30 लाख टन 240.00

औद्योगिक मजूदर 33 लाख टन 7.33

कुटीर उद्योग 40,000 टन 24.00

कुल 516.33

लेकिन अनेक मूल्य-संवर्धित उत्पादों का विनिर्माण जैसे लैमिनेटेड ब्रांड, बांस के रेशे के उत्पादन, बांस के रेशे के फाइबर सीमेंट बोर्ड बनाने, बांस की फर्श बनाने, दवाएं, खाद्य पदार्थ, लकड़ी के विकल्प, रोजगार के अवसर पैदा करने, आमदनी बढ़ाने के साथ-साथ उपलब्ध संसाधनों का चिरस्थाई उपयोग सुनिश्चित करने में किया जाता है। बांस पर आधारित टेक्नोलॉजी ने बहुत से उद्यमियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और देश में बांस-आधारित कुछ उद्योग पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। बांस के उपयोग कई प्रकार से किया जा सकता है इसलिए यह मूल्य-संवर्धन गतिविधियों के लिए उपयुक्त है। इससे मूल्य-संवर्धित वस्तुएं बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर पैदा किए जा सकते हैं। ग्रामीण रोजगार बढ़ाने में इसकी भूमिका का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि बांस लगाने में ही हर साल प्रति हेक्टेयर करीब 160 दिहाड़ियों का रोजगार पैदा होता है। एक टन बांस की कटाई में औसतन 8-10 दिहाड़ियों के बराबर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इसी तरह, इसके परिवहन और लादने-उतारने में 5 दिहाड़ियों का रोजगार मिलता है। बांस से उपयोगी सामान बनाने में, इस्तेमाल से पहले इसका प्रसंस्करण करने में 80 दिहाड़ियों का रोजगार पैदा होता है। कुटीर उद्योगों में एक टन बांस के प्रंस्करण में प्रति टन 600 दिहाड़ियों का रोजगार मिलता है। अध्ययनों पर आधारित निम्नलिखित आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि बांस-आधारित अर्थव्यवस्था की रोजगार क्षमता हर साल 516.33 दिहाड़ियों का रोजगार पैदा करने की है।

बांस की क्षमताओं की बड़ी उपेक्षा हुई है जिसकी वजह से यह क्षेत्र संगठित रूप से विकसित नहीं हो पाया है और इसके लिए बाजार सम्पर्क की सुविधा भी दयनीय है। उद्योग और हस्तशिल्पियों के स्तर पर इससे मूल्य-संवर्धित पदार्थ बनाने में टेक्नोलॉजी का उपयोग उपयुक्त-स्तर पर नहीं हो पाता।

बांस की क्षमताओं की पहचान करते हुए राष्ट्रीय बांस प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास मिशन 2003 की रिपोर्ट में बांस-आधारित अर्थव्यवस्था के उन्नयन की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। इसके लिए बांस के विकास को ग्रामीण आर्थिक विकास, गरीबी उपशमन, बांस-आधारित हस्तशिल्पों और औद्योगिक विकास के कार्य में नीतिगत भूमिका सौंपी गई है।

बांस की वाणिज्यिक खेती और इससे जुड़ी अन्य मूल्य-संवर्धन गतिविधियों में ग्रामीण लोगों को रोजगार दिलाने वाले आर्थिक संसाधन के रूप में बांस की क्षमता का नही के बराबर उपयोग हुआ है। इसका कारण यह है कि इस बारे में उपयुक्त नीति, बागानों के संस्थागत नेटवर्क, टेक्नोलॉजी उन्नयन, उत्पाद और बाजार -स्तर की कमी है। हमारे देश में बांस की उपयोग में नहीं की जा रही ऐसी व्यापक क्षमता है जिससे अर्थव्यवस्था में आमूल बदलाव लाया जा सकता है। बांस को वन से बाहर के क्षेत्रों में उगाने की भी जबर्दस्त संभावनाएं हैं क्योंकि:-

क) प्राकृतिक वनों की तुलना में ऐसे इलाकों में बांस के बागानों का प्रबंधन करना आसान होता है और

ख) उपयोग करने वाली एजेंसियों से नजदीकी होने के कारण बांस की कटाई किफायती लागत पर की जा सकती है।

आज भारत के सामने जमीन के खराब होने की समस्या सबसे गम्भीर है। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायनमेंट 2017 (भारत के पर्यावरण की स्थिति) नाम की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश की 30 प्रतिशत जमीन खराब हो चुकी है। इसे जोड़ने और ठीक करने की अपनी अनोखी क्षमता की वजह से बांस ऐसी जमीन को सुधारने के लिए सर्वोत्तम उपाय है।

अक्टूबर 2006 में शुरू किए गए राष्ट्रीय बांस मिशन (एन.एम.बी.) बांस की जबर्दस्त क्षमता का फायदा उठाने के कार्य में नया जोश पैदा करने और इसे नई दिशा देने की भारत सरकार की एक पहल है। यह बहु-विषयक और बहु-आयामी दृष्टिकोण है। इसके महत्त्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिन उपायों की योजना बनाई गई है, वे अनुसंधान और विकास, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों या ग्राम विकास समितियों के माध्यम से वन भूमि और गैर-वन भूमि पर बांस उगाने, किसान/महिला पौधशालाओं के जरिए उच्च गुणवत्ता वाली पादप सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने, बांस के हस्तशिल्प को बढ़ावा देने, इसके विपणन व निर्यात को बढ़ावा देने और बांस के थोक और खुदरा बाजारों की स्थापना पर केन्द्रित हैं।

राष्ट्रीय बांस मिशन को केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में 2006-07 में शुरू किया गया और तब से 3,61,791 हेक्टेयर भूमि पर बांस के बागान लगाए जा चुके हैं जिनमें से 2,36,700 हेक्टेयर वन क्षेत्र में और 1,25,091 हेक्टेयर गैर-वन भूमि में हैं। 91,715 हेक्टेयर पर मौजूदा बांस बागानों की उत्पादकता में सुधार किया गया है। उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 1,466 पौधशालाएं बनाई गई हैं। इस तरह की पौधशालाओं के प्रबंधन और बांस के बागान लगाने के लिए विभिन्न राज्यों में 61,126 किसानों और 12,710 क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा, गाँवों के पास बांस के 39 थोक और खुदरा बाजार बनाए गए हैं और 29 और फुटकर केन्द्र तथा 40 बांस मंडियां भी स्थापित की गई हैं।

लेकिन राष्ट्रीय बांस मिशन के अन्तर्गत 2006-17 की अवधि के दौरान 3.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र (जिसमें से 1.25 लाख हेक्टेयर गैर-वन क्षेत्र था) बांस की बागवानी के अन्तर्गत लाया गया, जबकि लक्ष्य दसवीं योजना में 20 लाख हेक्टेयर की वृद्धि करना और कुछ क्षेत्र को दसवीं और ग्यारहवीं योजना में 60 लाख टन करने का था। यह बात गौर करने की है कि गैर-वन क्षेत्र में उपलब्धियां क्षमता से काफी कम रही हैं।

भारतीय वन अधिनियम 1927 में बांस को 'वृक्ष' की श्रेणी में रखा गया था, जो कानून के अनुसार एक विरोधाभास है। इससे बांस के बागानों का विकास, खासतौर पर गैर-वन क्षेत्रों में अवरुद्ध हुआ। वर्ष 2017 के अंत तक वनों से बाहर के इलाकों में उगाया जाने वाला बांस, पेड़ों को काटने और उसके परिवहन के विनियामक नियमों के अन्तर्गत आता था। ऐसा महसूस किया गया कि राष्ट्रीय बांस मिशन का जोर, कुल मिलाकर बांस की बागवानी और उपज को बढ़ावा देने पर था और इसके प्रसंस्करण उत्पाद विकास और मूल्य संवर्धन के बहुत सीमित प्रयास किए गए। इससे बांस उगाने वालों और उद्योगों के बीच कमजोर सम्पर्क कायम हो सका।

आज देश में बांस उद्योग के समन्वित विकास की आवश्यकता है। भारत सरकार ने अप्रैल 2018 में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन को स्वीकृति प्रदान की जिसके अन्तर्गत अगले दो वर्षों में 1,290 करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान किया गया। इसमें बांस क्षेत्र के लिए पौधारोपण सामग्री से लेकर बागवानी, संग्रह सुविधा कायम करने, समेकन, प्रसंस्करण, विपणन, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों, कौशल विकास और ब्रांड कायम करने जैसी पहल के बारे में क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाते हुए सम्पूर्ण मूल्य-श्रृंखला विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इससे किसानों की आमदनी दोगुनी करने में मदद मिलेगी और कुशल और अकुशल कामगारों, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

किसानों को इन उपायों का फायदा मिले, इसके लिए वन क्षेत्र के बाहर बांस के स्टॉक को वृक्ष की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है। इसके लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2 (7) में भारत सरकार ने नवम्बर 2017 में संशोधन किया। इसके अलावा स्फूर्ति (स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजेनेरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज) नाम की योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है ताकि परम्परागत उद्योगों और बांस की दस्तकारी करने वाले हस्तशिल्पियों को बढ़ावा मिले। बांस संस्कृति की समुचित समझ और तकनीकी सहायता से एक ऐसी बांस क्रान्ति आ सकती है जिसमें बांस- आधारित उद्योगों के उत्थान की क्षमता है।

नई पहल

हिमाचल प्रदेश- बांस उत्पादन को वाणिज्यिक-स्तर पर बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य-स्तरीय बांस विकास एजेंसी गठित करने का फैसला किया है और उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बांस आर्थिक क्षेत्र भी बनाया है। हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बांस उगाने की जबर्दस्त सम्भावनाएं हैं जिसकी उद्योगों में बड़ी मांग है। ऐसे में बोर्ड के गठन से किसानों को उद्योगों में बांस की जबर्दस्त मांग को पूरा करने के लिए इसकी बागवानी को अपनाने में बड़ी मदद मिलेगी।

तेलंगाना सरकार ने किसानों को आमदनी का चिरस्थाई स्रोत उपलब्ध कराने के लिए जून, 2018 में 506 हेक्टेयर में (1,250 एकड़) भूमि पर बांस के बागान लगाने की परियोजना शुरू करने का फैसला किया।

महाराष्ट्र सरकार किसानों की आमदनी के स्रोत के रूप में बांस की बागवानी को बढ़ावा देने को बड़ी उत्सुक है। इसके लिए उसने अगस्त 2018 में महाराष्ट्र बांस विकास बोर्ड का गठन किया। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि वन विभाग की बजाय ग्रामीण समुदायों का बांस की बिक्री पर पूरा नियंत्रण रहे। यहाँ तक कि राज्य सरकार ने बांस अनुसंधान केन्द्र भी गठित किया है जिसके लिए धन की व्यवस्था आटा समूह द्वारा की जाती है।

जम्मू-कश्मीर में बांस मिशन 2021-22 के लिए 820 लाख रुपये की कार्य योजना राशि को मंजूरी दी गई है। कार्य योजना में बांस के प्रसार और खेती, उत्पाद विकास, उपकरण और मशीनरी का विकास, कौशल विकास और जागरूकता, बांच की खेती में अनुसंधान और विकास क्षेत्र पर काम किया जाएगा। मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने बांस मिशन के लिए यूटी स्तरीय कार्यकारी समिति (यूटीएलईसी) की बैठक में वार्षिक कार्य योजना राशि को मंजूरी दी है। चालू वित्त वर्ष में विभाग ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में 4.09 लाख पौधों की क्षमता के साथ 25 बांस नर्सरी स्थापित करने और उच्च घनत्व वाले बांस रोपण के तहत 1400 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने का प्रस्ताव है। विभाग विभिन्न कौशल विकास कार्यशालाओं और जागरूकता सृजन शिविरों के आयोजन के साथ दो टिशू कल्चर लैब, बांच शूट प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करेगा। इससे आय बढ़ाने के अलावा स्थानीय आबादी के लिए आजीविका के महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है। मुख्य सचिव ने कृषि विभाग को स्कास्ट के परामर्श में उत्पादकता वृदि और बेहतर कृषि पदतियों पर विशेष जोर देने पर बल दिया है। विभाग को आगे किसानों की आधार सीड जानकारी वन विभाग के साथ साझा करने और विभिन्न कल्याण सहायता और समर्थन को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

इससे पहले मोदी सरकार ने 31 अक्टूबर को गठित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विकास योजनाओं की शुरुआत की है. यहां के लोगों को बांस उगाकर कमाई करवाने की तैयारी है. इसकी खेती पर सरकार 50 फीसदी पैसा खुद दे रही है. इसके हर पौधे पर 120 रुपये देगी. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांस की खेती का कॉमर्शियल लाभ उठाने के लिए 3 बांस प्रौद्योगिकी पार्क बनाए जाएंगे. जम्मू-कश्मीर के कठुआ तथा तराई वाले जिलों में प्राकृतिक तौर पर बांस उगता है. इसलिए यहां के लोगों को प्रोफेशनल तरीके से इसकी खेती करने की सीख देने के लिए जम्मू, श्रीनगर और लेह में बैंबू टेक्नॉलोजी पार्क बनाने का प्रस्ताव है. सरकार की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के किसान बांस की खेती करके मोटा लाभ कमाएं और चैन की बंसी बजाएं.

सरकार ने बदला नियम- बांस काटने पर पहले फॉरेस्ट एक्ट लगता था. एफआईआर होती थी. फॉरेस्ट अधिकारी और पुलिस किसान को परेशान करते थे. इसलिए वो बांस लगाने से बचता था. लेकिन अब सरकार ने इस नियम को बदल दिया है. यही नहीं इसकी व्यापक पैमाने पर खेती के लिए राष्ट्रीय बैंबू मिशन भी बना दिया है. जिसके तहत किसान को बांस की खेती करने पर प्रति पौधा 120 रुपये की सरकारी सहायता भी मिलेगी.

बांस की खेती पर लागत हुई कम- कृषि मंत्रालय की एडिशनल सेक्रेटरी अल्का भार्गव के मुताबिक तीन साल में औसतन 240 रुपये प्रति प्लांट की लागत आती है. जिसमें से 120 रुपये प्रति प्लांट सरकारी सहायता मिलेगी.

नार्थ ईस्ट को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में इसकी खेती के लिए 50 फीसदी सरकार और 50 फीसदी किसान लगाएगा. 50 फीसदी सरकारी शेयर में 60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी राज्य की हिस्सेदारी होगी, जबकि नार्थ ईस्ट में 60 फीसदी सरकार और 40 फीसदी किसान लगाएगा. 60 फीसदी सरकारी पैसे में 90 फीसदी केंद्र और 10 फीसदी राज्य सरकार का शेयर होगा.

बांस की खेती से लाखों कमाने का मौका- जरूरत और प्रजाति के हिसाब से एक हेक्टेयर में 1500 से 2500 पौधे लगा सकते हैं. अगर आप 3 गुणा 2.5 मीटर पर पौधा लगाते हैं तो एक हेक्टेयर में करीब 1500 प्लांट लगेंगे. साथ में आप दो पौधों के बीच में बची जगह में दूसरी फसल उगा सकते हैं. 4 साल बाद 3 से 3.5 लाख रुपये की कमाई होने लगेगी.

हर साल रिप्लांटेशन करने की जरूरत नहीं. क्योंकि बांस की पौध करीब 40 साल तक चलती है.

दूसरी फसलों के साथ खेत की मेड़ पर 4 गुणा 4 मीटर पर यदि आप बांस लगाते हैं तो एक हेक्टेयर में चौथे साल से करीब 30 हजार रुपये की कमाई होने लगेगी.

इसकी खेती किसान का रिस्क फैक्टर कम करती है. क्योंकि किसान बांस के बीच दूसरी खेती भी कर सकता है. सरकारी नर्सरी से पौध फ्री मिलेगी.

बांस से क्या बना सकते हैं आप- इसकी 136 प्रजातियां हैं. अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग बांस की किस्में. लेकिन उनमें से 10 का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है. यह देखकर प्रजाति का चयन करना होगा कि आप किस काम के लिए बांस लगा रहे हैं.

अगर फर्नीचर के लिए लगा रहे हैं तो संबंधित प्रजाति का चयन करना होगा. बांस कंस्ट्रक्शन के काम आ रहा है. आप इससे घर बना सकते हैं, फ्लोरिंग कर सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, हैंडीक्रॉफ्ट और ज्वैलरी बनाकर कमाई कर सकते हैं.

बैंबू से अब साइकिलें भी बनने लगी हैं. अब शेड डालने के लिए सीमेंट की जगह बांस की सीट भी तैयार की जा रही है.

बैम्बू टेक्नोलॉजी पार्क के जरिए बांस की पैदावार, इससे बनने वाले प्रोडक्ट्स और इसकी मार्केटिंग की जानकारी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के किसानों को दी जाएगी.

भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत शीर्ष संगठ ट्राइफेड जनजातीय लोगों को बांस को जरा भी बर्बाद किए बिना उसका अनुकूलतम तरीके से इस्तेमाल करने और इससे अगरबत्ती, माचिस की डिब्बियां, कपड़ा आदि बनाने के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए संस्था खोलेगा। इससे जनजातीय लोगों की आमदनी बढ़ाने और हमारे बाजारों को मुक्त बनाने में मदद मिलेगी।

मिजोरम – एक रिपोर्ट के अनुसार जापान सरकार बांस उद्योग के विकास और सड़कों के निर्माण के लिए मिजोरम सरकार को मदद दे सकती है। इतना ही नहीं, जापान सरकार प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने में भी मदद कर सकती है। उसका जोर राज्य की बांस सम्पदा के मूल्य-संवर्धन के लिए एक उद्योग लगाने पर रहेगा। राज्य में किसी ऐसे बड़े उद्योग की कमी है जो उसके संसाधनों की क्षमता का फायदा उठा सके।

आगे की राह देश में जमीन के बंजर होने की रफ्तार में कमी लाने के लिए बांस उगाने के सघन कार्यक्रम को 2019-20 के बाद भी जारी रखने की आवश्यकता है और इसमें सभी सम्बद्ध पक्षों को शामिल किया जाना चाहिए।

चीन का अनुसरण करते हुए भारत सरकार को चाहिए कि वह बंजर भूमि और ढलान वाली जमीन में बांस के बागान लगाने में ग्रामीण किसानों को मदद दे।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत भी भवन सामग्री के रूप में बांस के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वजन उठाने में सक्षम संरचनात्मक घटक के रूप में बांस के विकास से ऊंची लागत वाले निर्माण कार्यों में इसके उपयोग का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। जिससे बांस की बागवानी को हमारे देश के विशाल बंजर क्षेत्र को हरा-भरा करने के आर्थिक रूप से व्यावहारिक तरीके के रूप में अपनाया जा सकेगा (स्मिता चुघ, बैम्बू-ए-ग्रीन ऑप्शन फॉर हाउसिंग)।

खाने योग्य बांस की पूर्वी एशियाई व्यजनों को बनाने और दवा के रूप में भारी मांग रहती है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में उगाए जाने वाला बांस (जो भारत में उगाए जाने वाले बांस की मात्रा का 66 प्रतिशत है) सरकार की मदद से ताइवान और जापान जैसे पूर्वी एशिया के देशों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर निर्यात किया जा सकता है।

अगरबत्ती उद्योग का भारत में बड़ा विस्तृत बाजार है। भारत वियतनाम और चीन से 35,000 टन गोल सीकें आयात करता है। इससे पहले उत्तर-पूर्वी राज्यों की हाथ की बांस की बनी चौकोर सींकों का अगरबत्ती बनाने में उपयोग किया जाता था। लेकिन जब टेक्नोलॉजी बदली और मशीनों का उपयोग होने लगा तो गोल सींकों को प्राथमिकता दी जाने लगी। भारत इस तरह की 3,000 टन सींकों का उत्पादन करता है। इस उद्योग को जिस किस्म की सींकों की जरूरत होती है, उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली बांस की खास प्रजाति का स्थानीय उत्पादन बढ़ाकर आवश्यकता पूरी की जा सकती है। यह भी देखा गया है कि करीब 13 प्रतिशत बांस बंग्लादेश और म्यांमार में अवैध रूप से भेजा जाता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, देश में बांस की कमी को देखते हुए इसे काफी बड़ी मात्रा में विदेशों से आयात करना पड़ता है। इस तरह के अवैध व्यापार पर तत्काल रोक लगाने की आवश्यकता है।

(लेखक का कृषि सम्बद्ध क्षेत्रों और पर्यावरण मुद्दों पर व्यापक अनुभव है। इससे पहले, योजना आयोग में उद्योग और खनिज, कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों आदि में विभिन्न पदों पर 25 साल से अधिक समय तक कार्य किया और हरियाणा पर्यावरण प्रबंधन सोसायटी के पूर्व मुख्य कार्यकारी भी रह चुके हैं।)

(Source एस.सी.लाहिड़ी; कुरुक्षेत्र,

- Compiled by: C M Sharma)